हिन्दी दैनिक

संयम भारत

18 वर्षों से प्रगति के पथ पर अग्रसर

वर्ष : 20 अंक : 72
नगर संस्करण, पृष्ठ - 4, मूल्य 1.00 रू0

उत्तर प्रदेश | शुक्रवार, 12 जून 2026 | प्रयागराज | विचार

राजनीति में मतभेद स्वीकार है, बेटियों का अपमान नहीं, सपा मुख्यालय के बाहर लगा होर्डिंग

जरूरी मुददों पर जनता का ध्यान भटकाने में जुटी हुई है भाजपा- मोना

धन्य आध्यात्मिक यात्रा-हज: अनुग्रह की दिव्य संरचना

किसान समृद्धि के 12 साल: पीएम मोदी बोले, 'टेक्नोलॉजी' से बदल रही किसानों की तकदीर

प्रधानमंत्री मोदी ने 'किसान समृद्धि योजना' की 12वीं वर्षगांठ पर PM-किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना और PM-कुसुम जैसी योजनाओं के माध्यम से किसानों की आय सुरक्षा और कृषि को सशक्त बनाने पर बल दिया। उन्होंने खेती में लागत कम करने और बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने वाली 'बीज से बाजार तक' पहल तथा तकनीक के उपयोग को भी सराहा।

एजेंसी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी, 2026 को किसानों की मदद करने वाली विभिन्न सरकारी पहलों के महत्व पर जोर देते हुए 'किसान समृद्धि योजना' की 12वीं वर्षगांठ मनाई। उन्होंने किसानों की आय की सुरक्षा और कृषि को मजबूत करने में PM-किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी प्रमुख कृषि कल्याण योजनाओं की भूमिका की सराहना की। पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे किसान भाई-बहन देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि का आधार हैं। उनकी ज़िंदगी को जितना हो सके आसान बनाने के लिए हमारी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। PM-किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहल न केवल उनकी आय को सुरक्षित कर रही हैं, बल्कि खेती को और मजबूत भी बना रही हैं। मोदी ने खेती-बाड़ी के क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली दूसरी योजनाओं का भी ज़िक्र किया और बताया कि PM-KUSUM योजना से किसानों को खेती के कामों के लिए सोलर एनर्जी मिल रही है, जिससे लागत कम हुई है। उन्होंने कहा कि PM-KUSUM योजना के जरिए उन्हें खेती के लिए सोलर एनर्जी मिल रही है और इससे जुड़ी लागत भी कम हुई है। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है, क्योंकि इससे उन्हें खेती और दूसरी जरूरी जरूरतों के लिए कम ब्याज दर पर आसानी से लोन मिल जाता है। इसके अलावा, पीएम मोदी ने सरकार की बीज से बाजार तक (From Seed to Market) पहल के बारे में बात की, जो फसलों के लिए सही दाम सुनिश्चित करने और खेती-बाड़ी की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी 'बीज से बाजार तक' पहल फसलों के लिए सही दाम सुनिश्चित करने में भी बहुत असरदार साबित हो रही है। किसानों का कल्याण हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने टेक्नोलॉजी पर आधारित तरीकों को अपनाकर खेती को आधुनिक बनाने की कोशिशों का भी ज़िक्र किया: ड्रोन, सॉइल हेल्थ कार्ड और प्राकृतिक खाद से जुड़ी पहल भी किसानों को फसल की पैदावार बढ़ाने में मदद कर रही हैं।

नीट पेपर लीक: खड़गे का मोदी सरकार पर वार, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़

एजेंसी

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने NEET पेपर लीक विवाद को लेकर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि बार-बार हो रही ऐसी घटनाओं ने लाखों युवाओं का भरोसा तोड़ा है और भारत की परीक्षा प्रणाली में गंभीर खामियों को उजागर किया है। खड़गे की यह टिप्पणी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) में कथित अनियमितताओं को लेकर फिर से शुरू हुई राजनीतिक बहस के बीच आई है। प्रश्न पत्र लीक होने और प्रक्रिया में गड़बड़ी के कई दावों के बाद से ही यह परीक्षा जांच के दायरे में है। इस मुद्दे ने छात्रों और विपक्षी दलों के बीच देशव्यापी चिंता पैदा कर दी है। इस स्थिति को गवर्नेंस की गहरी चुनौतियों का नतीजा बताते हुए खड़गे ने कहा कि देश की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिस्टम की विश्वसनीयता खतरे में है। उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार पेपर लीक होने के विवादों ने अहम परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के बीच कन्फ्यूजन, चिंता और अविश्वास पैदा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस विवाद की वजह से विरोध-प्रदर्शन और जवाबदेही की राजनीतिक मांगें भी उठी हैं, जिसमें विपक्षी नेताओं ने परीक्षा की सुरक्षा और भर्ती प्रक्रियाओं के मैनेजमेंट पर सवाल उठाए हैं। NEET से जुड़े आरोपों को अधिकारियों - जिसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी शामिल है - ने लगातार नकारा है या उनकी जांच की है। एजेंसी का कहना है कि परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के उपाय लागू हैं और कथित अनियमितताओं की जांच जारी है। NEET से जुड़ा विवाद एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि परीक्षा में बार-बार होने वाली गड़बड़ियों से भारत की शिक्षा व्यवस्था और लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है।

अब ममता के भतीजे पर भड़के कल्याण बनर्जी, कहा...

अपमान बर्दाश्त नहीं, दीदी मुझे चुने या अभिषेक को...

एजेंसी

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में अंदरूनी मतभेद

खुलकर सामने आ गए हैं। पार्टी सांसद और वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए उनके नेतृत्व और व्यवहार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मीडिया से बातचीत में कल्याण बनर्जी ने कहा कि वह अब अभिषेक बनर्जी से जुड़े किसी भी कानूनी मामले की पैरवी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें उनका घमंडी रवैया पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने वकालत के पेशे में 45 साल बिताए हैं और कई मौजूदा नेता कभी उनके जूनियर के रूप में काम कर चुके हैं। कल्याण बनर्जी ने कहा, अभिषेक बनर्जी मेरा अपमान नहीं कर सकते। राजनीति में भी मैं उनसे वरिष्ठ हूं। उन्हें यह समझना होगा कि उनकी वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है और आज पार्टी जिस संकट से गुजर रही है, उसके लिए भी वही जिम्मेदार हैं। उन्होंने आगे कहा कि वह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते और इस मुद्दे पर पार्टी प्रमुख एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी अपील करेंगे। कल्याण बनर्जी ने कहा, मैं दीदी से कहना चाहता हूं कि अगर आप अभिषेक बनर्जी पर ही निर्भर रहना चाहती हैं तो उन्हीं के साथ रहिए, मुझे छोड़ दीजिए।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, होममेकर्स को 'राष्ट्र निर्माता' मानकर 30,000 रु. मासिक मुआवजा

एजेंसी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने घर संभालने वाली महिलाओं को 'राष्ट्र निमार्ता' माना और बिना पैसे वाले घरेलू काम की आर्थिक अहमियत को स्वीकार किया। एक अहम फैसले में, शीर्ष अदालत ने कहा कि घरेलू देखभाल सेवाओं के नुकसान को 'मुआवजे का एक अलग आधार' माना जाना चाहिए और मोटर दुर्घटना के दावों में ऐसे नुकसान का आकलन करने के लिए 30,000 रुपये की अनुमानित मासिक आय तय की। जस्टिस संजय करोल और एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि घर संभालने वालों का योगदान सिर्फ.घर के कामों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि परिवार, समाज और अंततः देश को बनाने में भी उनकी अहम भूमिका होती है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि बिना वेतन वाले घरेलू काम को सिर्फ. इसलिए आर्थिक रूप से महत्वहीन नहीं माना जा सकता क्योंकि इससे कोई औपचारिक वेतन नहीं मिलता। कोर्ट ने कहा कि गृहिणियां घर में योगदान देती हैं। वे राष्ट्र-निमार्ता हैं। वे राष्ट्र का निर्माण करती हैं। जस्टिस करोल ने कहा कि हमारा भी यह मानना है कि गृहिणी व्यक्ति और राष्ट्र के विकास में योगदान देती है। घर संभालने वाली महिला राष्ट्र का निर्माण करती है। इसलिए हमने कुछ सिद्धांत तय किए हैं; एक राष्ट्र-निमार्ता के तौर पर गृहिणी की भूमिका को देखते हुए, हमने घरेलू देखभाल के नुकसान की न्यूनतम मासिक आय 30,000 रुपये प्रति माह तय की है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के पहले के उन फैसलों पर आधारित है - जैसे 'कीर्ति बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड' (2021) और 'अरुण कुमार अग्रवाल बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड' (2010) - जिनमें घर संभालने वालों (होममेकर्स) के काम को बिना पैसे वाला काम माने जाने के बावजूद उसकी आर्थिक अहमियत को माना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'घर की देखभाल न मिल पाने' को मुआवजे के एक अतिरिक्त और स्वतंत्र आधार के तौर पर माना जाना चाहिए। बेंच ने ऐसे नुकसान का आकलन करने के लिए 30,000 रुपये प्रति महीने की न्यूनतम काल्पनिक आय तय की।

टीएमसी को लगा एक और झटका, प्रकाश चिक बराइक ने दिया राज्यसभा से इस्तीफा

एजेंसी

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य प्रकाश चिक बराइक ने बृहस्पतिवार को उच्च सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस सप्ताह इस्तीफा देने वाले वह पार्टी के तीसरे सांसद हैं। सूत्रों के अनुसार, बराइक ने राज्यसभा के सभापति सी पी राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा। अपने इस्तीफे में पश्चिम बंगाल से सांसद बराइक ने लिखा, मैं राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देता हूं, जिसे कृपया तत्काल प्रभाव से स्वीकार किया जाए। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सहयोग के लिए सभापति, उपसभापति और राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों का भी आभार व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल के एक आदिवासी नेता बराइक उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण पर संसद की स्थायी समिति तथा जनजातीय मामलों की परामर्शदात्री समिति के सदस्य थे। उनका इस्तीफा ऐसे समय आया है जब तृणमूल कांग्रेस से लगातार इस्तीफे हो रहे हैं। सोमवार को राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय ने उच्च सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और बाद में तृणमूल नेतृत्व से मतभेदों का हवाला देते हुए पार्टी छोड़ने की घोषणा की थी। इसके बाद बुधवार को राज्यसभा सदस्य सुष्मिता देव ने संसद और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया।

अदालत ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक

एजेंसी

नई दिल्ली। कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता के चयन को लेकर हस्ताक्षर जालसाजी मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी को किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से बृहस्पतिवार को अंतरिम राहत प्रदान की। न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने तीन सप्ताह के लिए अंतरिम संरक्षण देते हुए बनर्जी को निर्देश दिया कि वह मामले में पूछताछ के लिए बृहस्पतिवार शाम छह बजे तक कोलकाता स्थित सीआईडी मुख्यालय भवानी भवन में उपस्थित हों। बनर्जी के वकील ने अदालत को बताया कि सांसद दिल्ली से कोलकाता लौट रहे हैं और उनका शाम करीब चार बजे पहुंचने का कार्यक्रम है।

निशिकांत दुबे का दावा: टीएमसी का खेल खत्म, 1-2 दिन में साफ होगा भविष्य!

एजेंसी

नई दिल्ली। बीजेपी के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने 11 जून को दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) जल्द ही खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी में चल रही राजनीतिक उथल-पुथल के बीच अगले कुछ दिनों में हालात और साफ हो जाएंगे। झारखंड के देवघर में अठकसे बात करते हुए, दुबे ने ममता बनर्जी की अगुवाई वाली पार्टी के भविष्य के बारे में अपनी पिछली बातों का ज़िक्र किया और तेजी से हो रहे राजनीतिक बदलावों की ओर इशारा करते हुए कहा कि बाबा की नगरी में कही गई हर बात सच साबित होती है। 1-2 दिनों में हमें और जानकारी मिल जाएगी। उनके ये बयान टीएमसी के अंदर चल रही आपसी कलह के बीच आए हैं, जहाँ कई इस्तीफे हुए हैं, गुटबाजी के आरोप लगे हैं और सीनियर नेताओं के बीच सार्वजनिक मतभेद सामने आए हैं।

ताजा मामला तब हुआ जब टीएमसी के सीनियर सांसद और वकील कल्याण बनर्जी ने एक कानूनी मामले को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की सार्वजनिक रूप से आलोचना की और उन पर "अहंकारी रवैया" दिखाने का आरोप लगाया। कल्याण बनर्जी ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को अल्टीमेटम दिया और उनसे कहा कि वे उनके और अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी में से किसी एक को चुनें। साथ ही, उन्होंने घोषणा की कि वे अब अभिषेक बनर्जी की ओर से कानूनी मामले नहीं देखेंगे। राज्यसभा से इस्तीफों के सिलसिले में बुधवार को टीएमसी सांसद प्रकाश चिक बारिक ने भी इस्तीफा दे दिया। सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर राय के बाद, वे एक हफ़्ते के अंदर ऊपरी सदन से इस्तीफा देने वाले तीसरे टीएमसी सांसद बन गए। इस बीच, बागी टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने दावा किया कि 20 सांसदों के एक समूह ने लोकसभा में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की और NDA के प्रति समर्थन जताया। हालांकि, टीएमसी की लोकसभा सांसद प्रतिमा मंडल ने इस कथित कदम से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया, बागी गुट को उनके हस्ताक्षर वाला कोई भी दस्तावेज पेश करने की चुनौती दी, पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा दोहराई और कहा कि वे 2029 तक तृणमूल कांग्रेस के साथ बनी रहेंगी।

अखिलेश यादव के ट्वीट को गंभीरता से नहीं लेती जनता: पीयूष गोयल

संवाददाता

लखनऊ। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लखनऊ में कहा है कि जनता एक बार फिर अखिलेश यादव को ठुकराएगी। यूपी की जनता उनको सीरियस नहीं लेती। यूपी की जनता न तो अखिलेश यादव के ट्वीट को गंभीरता से लेती है और न ही उन पर विश्वास करती है। मेरा मानना है कि जिस तरह से उन्होंने यूपी को विकास से वंचित रखा, कानून व्यवस्था बिगड़ने दिया, विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा दिया और पूरे राज्य में संतुलित विकास सुनिश्चित करने में विफल रहे, उसे जनता ने भुलाया नहीं है। पीयूष गोयल मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर गुरुवार को लखनऊ महानगर भाजपा की ओर से कराए गए प्रबुद्ध जन विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में पहुंचे। यहां उनके पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का दौरा किया। इस दौरान साथ मेयर सुषमा खर्कवाल, भाजपा नेता नीरज सिंह, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी सहित कई नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम से उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

एसटीएफ की बड़ी कामयाबी, जॉर्जिया से भारत लाया गया हरियाणा का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर

एजेंसी

नई दिल्ली। हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए कुख्यात गैंगस्टर वैनकेट गर्ग को जॉर्जिया से भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। यह पहली बार है जब जॉर्जिया से किसी आरोपी का भारत को प्रत्यर्पण हुआ है। इसके साथ ही वर्ष 2026 में हरियाणा एसटीएफ द्वारा सुनिश्चित किया गया यह 10वां निर्वासन या प्रत्यर्पण बन गया है। एसटीएफ के अनुसार 29 वर्षीय वैनकेट गर्ग अंबाला जिले के नारायणगढ़ क्षेत्र का रहने वाला है और करीब 53 सदस्यों वाले आपराधिक नेटवर्क का सरगना माना जाता है। गैंग पर अंबाला,

यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकूला और चंडीगढ़ में हत्या, लक्षित हमले, हत्या के प्रयास, रंगदारी वसूली, संगठित अपराध और अवैध हथियारों के इस्तेमाल जैसे मामलों में संलिप्त रहने के आरोप हैं। एसटीएफ जांच में सामने आया कि वैनकेट गर्ग 10 दिसंबर, 2024 को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) भाग गया था। बाद में 26 जनवरी, 2025 को वह जॉर्जिया पहुंच गया। जांच एजेंसियों को यह भी पता चला कि उसने गुरुग्राम के एक फ्लैट का गलत पता दिखाकर कथित तौर पर धोखाधड़ी से पासपोर्ट हासिल किया था। इस मामले में थाना नारायणगढ़ में अलग आपराधिक मामला दर्ज किया गया और एसटीएफ की सिफारिश पर फरवरी 2025 में उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया।

एफआईआर नहीं तो कार्रवाई क्यो? राज्यसभा नामांकन पर ओवैसी ने ईसी को घेरा

एजेंसी

नई दिल्ली। एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को चुनाव आयोग द्वारा मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द करने की प्रक्रिया पर चिंता जताई। मीडिया से बात करते हुए ओवैसी ने सवाल किया कि चुनाव आयोग के नामांकन फॉर्म के नियम के अनुसार, अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज है, तो आपको इसकी जानकारी देनी होती है। अब, उनका कहना है कि कोई एफआईआर नहीं है। इस मामले में, आगे क्या कदम उठाए जाएं, इसके लिए चुनाव आयोग से सलाह लेनी होगी। उन्होंने राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी के उस पुराने बयान का

ज़िक्र किया जिसमें कहा गया था कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं है और यह मामला सिर्फ.एक निजी शिकायत से जुड़ा है। ओवैसी ने कहा कि अगर कोई एफआईआर ही नहीं है, तो क्या कार्रवाई की जा सकती है? पहले बीएनएसएस के तहत, अगर आप कोर्ट में शिकायत करते थे, तो कोर्ट उसे आगे भेजकर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे सकता था। अब ऐसा नहीं है। ओवैसी ने आगे कहा कि सिंघवी के हवाले से आई मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, नटराजन के खिलाफ अभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, बल्कि सिर्फ.एक प्राइवेट शिकायत है और उन्हें कोर्ट में पेश होने का नोटिस मिला है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरी सच्चाई तो नहीं पता, लेकिन मैंने जो सुना और अखबारों में पढ़ा है, उसके अनुसार सिंघवी का कहना है कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है। ये टिप्पणियां राज्यसभा नामांकन के लिए पात्रता मानदंडों और इस प्रक्रिया के दौरान लंबित शिकायतों या कानूनी मामलों से निपटने के तरीकों को लेकर चल रही बहस के बीच आई हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि नामांकन दाखिल करते समय एफआईआर सहित सभी जरूरी जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन के नॉमिनेशन (नामांकन) के रद्द होने पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस का दस-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला।

● एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द होने पर चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए, तर्क दिया कि बिना एफआईआर के क्या कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केवल एक निजी शिकायत के आधार पर नामांकन खारिज करना नामांकन पात्रता मानदंडों पर गहन विचार की मांग करता है।

सम्पादकीय...

भाखड़ा का जल स्तर

हमारे नीति-नियंता आमतौर पर तब जागते हैं जब समस्या सिर पर आ जाती है। यदि समय रहते तंत्र, सजगता और सतर्कता से आसन्न संकट को महसूस करते हुए तत्काल रणनीति बनाकर कार्रवाई करता है, तो जन-धन की हानि को टाला जा सकता है। निस्संदेह, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी बीबीएमबी ने पंजाब और हरियाणा को भाखड़ा जलाशय से ज्यादा पानी निकालने की सलाह दी है। निश्चित रूप से इस सलाह को उत्तर भारत क्षेत्र में पानी के प्रबंधन से जुड़ी बढ़ती मुश्किलों के प्रति एक चेतावनी के रूप में देखी जानी चाहिए। निस्संदेह, यह सलाह रोजमर्रा के परिचालन से जुड़ा मामला भी नहीं है। इसे व्यापक संदर्भों में देखें तो लगातार बढ़ती जलवायु की अनिश्चितता, खेती से जुड़े ऐसे तौर-तरीकों, जिनका दीर्घकालीन उपयोग नहीं किया जा सकता है, के बाबत यह सलाह चेताती है। निश्चित रूप से यह सलाह यह भी बताती है कि पंजाब व हरियाणा में पानी के बेहतर उपयोग को लेकर सहमति न बनने से भी इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं। बांध प्रबंधन से जुड़े सूत्र बताते हैं कि भाखड़ा जलाशय का जलस्तर फिलहाल पिछले साल में इसी अवधि के दौरान के जलस्तर के मुकाबले 21 फीट अधिक है। वहीं दूसरी ओर जलाशय के अधिकतम जलस्तर तक पहुंचने में अब सिर्फ 102 फीट की जगह ही बची है। निश्चित रूप से इस दिशा में समय रहते ही अविलंब कार्रवाई करनी होगी। अन्यथा मानसून के आने के साथ वैकल्पिक उपायों की गुंजाइश भी लगातार कम होती जाती है। जलवायु परिवर्तन के गहरे होते प्रभावों के चलते हिमालयी पर्वत शृंखला में अधिक बर्फ के पिघलने की बढ़ती गति और बारिश के पैटर्न में लगातार आ रहे बदलाव के कारण ही जलाशय के जलस्तर में तेजी से बदलाव आने की आशंका भी बनी रहती है। यही वजह है कि इन तमाम आशंकाओं के मद्देनजर ही अविलंब नीतिगत फैसले लेने की सख्त जरूरत है। यह विडंबना ही है कि यह चुनौती पंजाब में ऐसे समय में आ रही है, जब धान की रोपाई का मौसम चल रहा है। हालांकि, राज्य में सरकार ने पानी के बेहतर इस्तेमाल के मद्देनजर धान की खेती का कैलेंडर एक जून तक के लिये आगे बढ़ा दिया था। यह भी गौरतलब है कि आज भी पंजाब के बड़े इलाकों में खेती काफी हद तक भूजल पर ही निर्भर है। जिस सीमा तक नहरों के नेटवर्क का अधिकतम उपयोग होना चाहिए था, वह अभी भी नहीं हो पा रहा है। निस्संदेह, जब तक सतही पानी का सही तरीके से बंटवारा नहीं होता है तब तक जलाशयों में ज्यादा पानी जमा करके रखना पड़ेगा। जिसके चलते अचानक आने वाले पानी को संभालने के लिये जरूरी बाढ़ बचाव क्षमता कम हो जाती है। हमें वर्ष 2023 में पंजाब में आई विनाशकारी बाढ़ से मिले सबक को नहीं भूलना चाहिए। तब पानी छोड़ने में कथित देरी और जलाशयों के संचालन को लेकर हुए तमाम विवादों ने राजनीतिक कड़वाहट को बढ़ाया ही था। साथ ही सरकार की बाढ़ से निबटने की तैयारियों को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े हुए थे। जब बांध प्रबंधन की बात करते हैं तो इसका मकसद सिर्फ बिजली उत्पादन ही नहीं हो सकता। तब बाढ़ को नियंत्रित करना भी उतना ही जरूरी मकसद होना चाहिए। ऐसे वक्त में हमें जरूरी कामों की प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। सिंचाई विभाग को सुनिश्चित करना ही होगा कि नहर का पानी किसानों को समय पर मिले। खासकर उन किसानों को जिनके खेत नहर के अंतिम छोर पर स्थित हैं। इससे हमारी जमीन के ऊपर मौजूद पानी के स्रोतों पर निर्भरता ज्यादा बढ़ेगी। साथ ही इन कदमों से जमीन के भीतर के पानी के भंडारों पर दबाव भी कम हो सकेगा। इसके साथ ही, सहयोगी राज्यों के साथ जलाशयों के कामकाज में पारदर्शिता और दूरदर्शिता के साथ तालमेल बैठाना होगा। पानी की भरपूर उपलब्धता से मुश्किल हालात का सामना करने की क्षमता बढ़नी चाहिए, न कि जोखिम को बढ़ावा दिया जाए। आज जलाशयों में जगह खाली करना भविष्य में मौसम से जुड़ी अनिश्चितताओं से निबटने के लिये सबसे अच्छा उपाय साबित हो सकता है।

राशिफल

मेषः- भावना से उद्वेलित मन निकट संबंधों के सुख-दुख के प्रति चिंतित होगा। पूर्वाग्रहवश संबंधियों के प्रति नकारात्मकता को न पालें। भविष्य संबंधी कुछ चिंताएं मन में नकारात्मक विचार ला सकती हैं।

बृषभ :- भौतिक महत्वकांक्षाएं अभाव का एहसास कराएंगी। परिजनों से कुछ भावनात्मक अपेक्षाएं कष्टकारी हो सकती हैं। अच्छी योजनाओ द्वारा महत्वपूर्ण कायरें को समयानुकूल पूर्ण करेंगे।

मिथुन :- भावनाओं पर नियंतण्रख अपने दायित्वों के प्रति सजग होना प्रगति का सूचक है। बचकाना स्वभाव महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एकाग्रता का अभाव पैदा करेगा। शिक्षा-प्रतियोगिता में परिश्रम का लाभ मिलेगा।

कर्क :- महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां अपनी पूर्ति हेतु मन पर दबाव बनाएंगी। कुछ नयी आकांक्षाएं मन पर प्रभावी होंगी। भौतिक-सुख साधन में व्यय संभव। परिजनों से किसी प्रकार की शिकायत पर खुलकर बात करें।

सिंह :- किसी श्रेष्ठजन के प्यार से मन प्रसन्न होगा। किसी की कटु वाणी मन को दुखित कर सकती है। उच्च महत्वकांक्षाएं व्यावसायिक क्षेत्र में अधिक परिश्रम के लिए प्रेरित करेंगी। आलस्य कतई न करें।

कन्याः- नये संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी। पारिवारिक वातावरण सुखद व उत्साहपूर्ण होगा। जीविका क्षेत्र में मन आर्थिक सुदृढ़ता हेतु प्रयत्नशील होगा। रोजगार में व्यस्तता रहेगी किंतु जरूरी कार्य समय से पूर्ण करें।

तुलाः- कुछ नयी अभिलाषाएं आपको उत्साहित करेंगी। शासन-सत्ता की दिशा में केंद्रित लोगों को लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। किसी महत्वपूर्ण दायित्व की पूर्ति हेतु समुचित व्यवस्था हेतु मन चिंतित होगा।

वृश्चिकः- किसी पुराने संबंध के प्रति विशेष निकटता की अनुभूति करेंगे। क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां अर्थिक सुदृढ़ता हेतु प्रेरित करेंगी। भावनाप्रधान मन रिश्तों से सहज ही प्रभावित हो जाता है।

धनुः- रोजगार क्षेत्र में आपकी महत्वपूर्ण योजनाएं सार्थक होती हुई नजर आएंगी। श्रेष्ठजनों से नजदीकियां पैदा होंगी। व्यावसायिक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। कुछ प्रबल इच्छाएं आपको उद्वेलित करेंगी।

मकरः- सामाजिक गतिविधियों में आपकी क्रियाशीलता बढ़ेगी। अच्छी भावनात्मक अभिव्यक्ति से संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा।

कुंभः- पुरानी समस्याओं को हल कर सुख की अनुभूति करेंगे। शासन-सत्ता से जुड़े लोगों को लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। पूजा-पाठ में पूरा दिन मन केंद्रित होगा। नये दायित्वों की पूर्ति होगी।

मीनः- पिता के सहयोग से मुश्किल दिनों में राहत मिलेगी। बालसुलभता व असंयमित शब्दों का प्रयोग संबंधों में कटुता लाएगा। आकस्मिक नई आशंकाओं से प्रभावित मन कोई गलत निर्णय ले सकता है।

बारह साल बेमिसाल की गठरी खुल गई

सर्वमित्रा सुरजन

चिराग पासवान, एकनाथ शिंदे, प्रफुल्ल पटेल न जाने क्यों पीछे रह गए। इन लोगों की लेखनी भी नरेन्द्र मोदी की बारह साला उपलब्धियों पर प्रकाश डालती तो एनडीए की एकजुटता पर पूरा ठप्पा लग जाता और मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी बढ़ाने की चापलूसी भी पूरी हो जाती। बस अब एक बात की कसर रह गई है कि बारह साल के लिए कोई नयी उपमा गढ़ ली जाए। अब तक रजत, स्वर्ण, हीरक जयंती ही सुना करते थे। इन महंगी धातुओं के समान बेशकीमती साल का बखान हुआ करता था। इस समय तो सोना-चांदी तो दूर की...

1947 में नेहरूजी के साथ सरदार पटेल, डॉ. अंबेडकर, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, सी. राजगोपालाचारी और मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे दिग्गजों ने सत्ता संभाली थी। हरेक की अपनी अलग हस्ती, अलग पहचान, अलग रूतबा। कोई किसी से कम नहीं और किसी ने किसी से तुलना नहीं की। यहां तक इनमें से किसी को नेहरू के नाम की टेक लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर इस समय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सत्ता पर 12 साल पूरे करने की खुशियां उमड़ी जा रही हैं। एक पुराने गीत की पंक्तियां हैं, मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में न समाए, पलक बंद कर लूं, कहीं छलक ही न जाए, बस इसी कृतज्ञ भाव से कई टीवी पत्रकार बारह साल, बेमिसाल के इर्द-गिर्द कार्यक्रम कर रहे हैं। भले ही बारह सालों की उपलब्धियों को तलाशना भूसे के ढेर में सुई तलाशने जैसा कठिन काम हो, फिर भी मालिक को खुश करने के लिए सारी तकलीफें उठाई जा रही हैं। कलाकारों को भी इसी काम में जोत दिया गया है। शो मैन कहे जाने वाले सुभाष घई बता रहे हैं कि 2014 से पहले देश के हालात कितने बुरे थे और अब मोदीजी के आने से लोगों का यकीन काफी बढ़ चुका है। उनके जैसे कई और राष्ट्रवादी कलाकारों ने ऐसी ही स्क्रिप्ट पढ़कर सोशल मीडिया पर संवाद अदायगी की है। देश भर के मंदिरों में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, पदाधिकारियों ने पूजा की, पता नहीं एक साथ सबको कैसे एक जैसे काम सूझते हैं, या फिर ये लोग भी स्क्रिप्ट पर ही काम करते हैं। मोदी मंत्रिमंडल के लोग तो बारह सालों के कसीदे काढ़ते हुए लेख लिख ही रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के लेख भी अखबार में आ गए। चिराग पासवान, एकनाथ शिंदे,

प्रफुल्ल पटेल न जाने क्यों पीछे रह गए। इन लोगों की लेखनी भी नरेन्द्र मोदी की बारह साला उपलब्धियों पर प्रकाश डालती तो एनडीए की एकजुटता पर पूरा ठप्पा लग जाता और मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी बढ़ाने की चापलूसी भी पूरी हो जाती। बस अब एक बात की कसर रह गई है कि बारह साल के लिए कोई नयी उपमा गढ़ ली जाए। अब तक रजत, स्वर्ण, हीरक जयंती ही सुना करते थे। इन महंगी धातुओं के समान बेशकीमती साल का बखान हुआ करता था। इस समय तो सोना-चांदी तो दूर की बात पेट्रोल भी बेशकीमती हो चुका है और गेहूं, दाल, चावल भी। तो अब मोदीजी ही तय कर लें कि अब से किसी भी चीज के बारह साल पूरे हों तो उसे पेट्रोल जयंती के तौर पर मनाया जाए या गेहूं, चावल के तौर पर। वो चाहें तो इसे मशरूम या मखाना जयंती भी कह सकते हैं। असल में मोदीजी के प्रचारक एक चूक कर गए। अगर वे बारह साल के लिए पहले ही कोई उपमा गढ़ लेते तो फिर नेहरूजी का नाम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सोचिए कितनी बेचारगी है नरेन्द्र मोदी की, कि कुछ भी कर लें नेहरूजी के नाम से पीछा ही नहीं छूटता। अभी बारह साल का जश्न भी तो इसीलिए मनाया जा रहा है क्योंकि नेहरूजी से ज्यादा दिनों तक शासन करने का रिकार्ड बना लिया। यानी कितना भी नेहरू को कोस लें, पैमाना वही रहेंगे। लेकिन केवल सत्ता पर बैठने का पैमाना क्यों तय करना है। 12 साल तक क्या किया, इसका भी हिसाब तो होना चाहिए। फकीर को इस बात से फर्क क्यों पड़ना चाहिए कि उसने कितने दिनों शासन संभाला। मोदीजी के राज्य गुजरात से ही आने वाले कथावाचक मोरारी बापू की सुनाई एक कथा याद आती है। खुद को संत मानने वाले एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को भी भगवद भक्ति की राह पर चलाना चाहा। इसके लिए सारी मोह-माया का त्याग करना जरूरी था। संत घर-द्वार छुड़वाकर अपनी पत्नी को संग लेकर वन की तरफ चल पड़े, रास्ते में उन्हें एक स्वर्ण मुद्रा गिरी हुई दिखी। उन्होंने फौरन उस पर मिट्टी डाल दी कि पत्नी कहीं इस के मोह में न पड़ जाए। लेकिन संत को स्वर्ण मुद्रा पर मिट्टी डालते देख पत्नी ने पूछा कि स्वामी आपने मिट्टी पर मिट्टी किस प्रयोजन से डाली। पत्नी की इस बात को सुनते ही संत को अपने ओछेपन का अहसास हुआ कि दूसरों को मोह-माया से निकालने का दावा करने वाले वे खुद अब तक इस जाल में फंसे हुए हैं। जबकि उनकी पत्नी जिसने सांसारिक सुखों से मुंह मोड़ने का कभी दावा नहीं किया, वो गृहस्थी के अपने सारे कर्तव्य निभाते हुए भी लोभ-मोह से मुक्त थी। हमें नहीं मालूम कि मोदीजी ने कभी ऐसी कोई कथा मोरारी बापू से सुनी या नहीं, लेकिन क्या वो अपनी फकीरी के दावे पर खरे उतर रहे हैं, यह अब जनता ही तय करे। वैसे राजनीति में नया चलन आ गया है कि सत्ता पर बैठने के सौ दिनों का जश्न मनाया जाए, साल भर पूरा हो जाए तो उसमें भी डंका पीटा जाए और पांच साल पूरे होने के बाद जनता दोबारा मौका दे, तब तो बात ही क्या है। इस लिहाज से देखें तो मोदीजी दो कार्यकाल पूरा करने के बाद तीसरी बार सत्ता पर बैठे तो 2024 में इसका जश्न मनाना सही था। लेकिन फिर अगले जश्न की बारी तो 2029 में आती, अगर जनता फिर से उन्हें चुनती। लेकिन 15 साल पूरे होने से पहले 12 साल में ही जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि नेहरूजी से आगे निकल गए हैं। मगर जैसे मोदीजी की शिक्षा, स्टेशन पर चाय बेचने और वैवाहिक स्थिति से लेकर काला धन वापिस लाने, हर खाते में 15 लाख रूपए डालने, अर्थव्यवस्था में लंबी छलांग लगाने जैसे कई वादों और दावों में भारी गफलत है, वैसी ही बड़ी गड़बड़ 12 साल तक सत्ता पर काबिज रहने के रिकॉर्ड में भी दिख रही है। पं.नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और उन्होंने 14-15 अगस्त की अर्द्धरात्रि को भाषण इसी हैसियत से दिया था। 15 अगस्त 1947 से लेकर अपनी मृत्यु 27 मई 1964 तक उन्होंने देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला। कुल 16 बरस 286 दिन यानी 6,130 दिन तक वे प्रधानमंत्री बने रहे। तो फिर भाजपा नेहरूजी की सत्ता के कम से कम 4 बरसों को खारिज क्यों कर रही है। क्या केवल इसलिए कि पहले आम चुनाव 1952 में हुए और भाजपा की गिनती तभी से शुरू हुई है। क्या इस तरह भाजपा 1952 के पहले के आजाद भारत के वर्षों को मान्यता नहीं देती है। और सबसे बड़ा सवाल क्या भाजपा यह जानती है कि नरेन्द्र मोदी ले देकर 15 साल सत्ता के पूरे कर भी लें, तो 16वें साल में उनकी विदाई हो जाएगी। 2024 का डर क्या अब तक भाजपा में कायम है, जब 240 सीटों पर इंडिया ब्लॉक ने उसे रोक दिया, जबकि दावा 4 सौ पार का था। किस हड़बड़ी में भाजपा संसदीय दल की बैठक बुलाए बिना एनडीए के सहयोगियों की मदद से नरेन्द्र मोदी ने खुद को प्रधानमंत्री घोषित करवाया, यह सबने देखा है। नेहरूजी को तो ऐसा करने की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ी। 1952, 57 और 62 में उन्हें पूर्ण बहुमत मिला। केबिनेट के मामले में भी मोदी नेहरूजी से कभी मुकाबला कर ही नहीं पाएंगे। 1947 में नेहरूजी के साथ सरदार पटेल, डॉ. अंबेडकर, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, सी. राजगोपालाचारी और मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे दिग्गजों ने सत्ता संभाली थी। हरेक की अपनी अलग हस्ती, अलग पहचान, अलग रूतबा। कोई किसी से कम नहीं और किसी ने किसी से तुलना नहीं की।

कुछ खास...

धन्य आध्यात्मिक यात्रा-हज: अनुग्रह की दिव्य संरचना

असद मिर्जा

अंतिम तीर्थयात्रा के द्वार पर खड़ा होना आत्मा की उस सूक्ष्म कंपन को महसूस करना है, जो उड़ान भरने से पहले एक पक्षी के पंखों में होती है। यदि पवित्र यात्रा के आरंभ पर आपका हृदय तेजी से धड़कने लगे, तो यह जानकर संतोष करें कि यह चिंता दरअसल आपके अहंकार का उस यात्रा के सामने झुकना है, जिसे मानव बुद्धि पूरी तरह समझ नहीं सकती। हर मुसलमान के लिए जीवन में एक बार हज पर जाना सबसे प्रिय स्वप्न होता है। इस स्वप्न को साकार करने के लिए लोग वर्षों तक परिश्रम करते हैं और अपनी बचत का एक-एक पैसा हज निधि में जोड़ते हैं। अंततः वे अल्लाह के आदेश और अपनी जीवन भर की आकांक्षा को पूरा करने के लिए इस यात्रा पर निकलते हैं। पंद्रह दिन पहले मैं बौद्धिक धारणाओं और पूर्वाग्रहों का बोझ लेकर रवाना हुआ था; लेकिन जब लौटा तो अपने भीतर ऐसे आयामों को खोज चुका था जिनके अस्तित्व से भी अनजान था। मैं टूटा भी था और पूर्ण भी। यही इस आध्यात्मिक साधना का वास्तविक और अवर्णनीय विरोधाभास है। कोई भी पुस्तक, कोई भी यात्रा कार्यक्रम उस गहन अनुभूति को व्यक्त नहीं कर सकता जो पहली बार पवित्र काबा—मानो समस्त ब्रह्मांड का केंद्र—को मस्जिद-ए-हरम के विशाल विस्तार में देखकर होती है। इसी प्रकार कोई मार्गदर्शिका किसी व्यक्ति को उस गहन विनम्रता और असहायता के लिए तैयार नहीं कर सकती जो उसे तब अनुभव होती है जब वह अपने शरीर को इहराम की सादी, बिना सिली हुई सफेद चादरों में लपेटता है। इन कठिन शारीरिक अनुष्ठानों से परे, हज का वास्तविक संघर्ष पूरी तरह आंतरिक होता है। जब आप लाखों लोगों के अथाह समुद्र में स्वयं को पाते हैं, तो आपके धैर्य, व्यवस्था और आत्मनियंत्रण के सारे भ्रम धीरे-धीरे टूटने लगते हैं। मैं आज भी उस संतुलन की तलाश में हूं, लेकिन मक्का के उन व्यस्त, सुंदर और अविस्मरणीय दिनों में जो जीवन-सूत्र मिले, वे आज भी मेरे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं।

पवित्र यात्री के दस सिद्धांत-

अपेक्षाओं का पूर्ण त्याग

इतने विशाल मानव समुदाय की मेजबानी का अर्थ है कि सबसे सुव्यवस्थित योजनाएं भी कभी न कभी अव्यवस्था में बदल सकती हैं। इसलिए परिस्थितियों से संघर्ष न करें। हज में बिना किसी अपेक्षा के प्रवेश करें और हर प्रशासनिक कठिनाई को बाधा नहीं, बल्कि अल्लाह की ओर से समर्पण का अवसर समझें।

अपने उद्देश्य को दृढ़ रखें

हम रेगिस्तानों को पार केवल भावनात्मक रोमांच या किसी असाधारण आध्यात्मिक अनुभव की तलाश में नहीं करते। हम हज इसलिए करते हैं क्योंकि यह एक पवित्र और अनिवार्य कर्तव्य है। इसकी वास्तविक महत्ता इसके प्रदर्शन में नहीं, बल्कि इसे पूर्ण करने में है और उससे प्राप्त शिक्षाओं को जीवन में उतारने में है।

निरंतर आध्यात्मिक परमानंद की अपेक्षा न करें

यह मान लेना कि आप या आपके आसपास के लोग हर समय आध्यात्मिक आनंद की अवस्था में रहेंगे, एक भ्रम है। आप भी मांस और हड्डियों से बने इंसान हैं। थकान और कठिनाइयों के बीच लगातार अलौकिक अनुभव की अपेक्षा करना वास्तविकता से दूर है।

धैर्य को अपना स्वभाव बनाइए

आप पूरी मानवता के प्रतिनिधियों के साथ चल रहे होते हैं, जिनकी संस्कृतियां, आदतें और व्यवहार अलग-अलग हैं। यदि किसी का व्यवहार आपको परेशान करे, तो पहले अपने भीतर झांकिए। अपने मार्ग पर चलते रहिए और दूसरों के आचरण का निर्णय करने से बचिए।

शारीरिक तैयारी और व्यावहारिक सावधानियां:-

तवाफ के दौरान सतर्कता

तवाफ के समय भीड़ का प्रवाह अत्यंत गतिशील होता है। यहां एक क्षण की असावधानी भी कठिनाई उत्पन्न कर सकती है। इसलिए निरंतर सजग रहें और अचानक रुकने या दिशा बदलने से बचें।

निरंतर गति का सिद्धांत

यदि तवाफ के दौरान कोई वस्तु हाथ से गिर जाए, तो उसे तुरंत उठाने का प्रयास न करें। लाखों लोगों की भीड़ में अचानक रुकना स्वयं और दूसरों के लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है। पहले अपना तवाफ पूरा करें, फिर सहायता लेकर वस्तु खोजने का प्रयास करें।

पर्याप्त जल और ऊर्जा बनाए रखें

तेज गर्मी और लंबी पैदल यात्राएं आपकी शारीरिक शक्ति को अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से कम कर देती हैं। इसलिए हमेशा पानी साथ रखें और खजूर, बिस्कुट अथवा अन्य ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थों का उपयोग करें। अत्यधिक पसीने की स्थिति में इलेक्ट्रोलाइट्स का सेवन भी लाभदायक हो सकता है।

शारीरिक असुविधा से बचाव

इहराम पहनकर लंबे समय तक पैदल चलना और धूप में रहना शरीर पर अतिरिक्त दबाव डालता है। त्वचा में घर्षण और छिलन जैसी छोटी समस्याएं भी बड़ी परेशानी बन सकती हैं। इसलिए पहले से सुरक्षात्मक क्रीम या अन्य उपाय अपनाएं।

अतिरिक्त चप्पल या जूते रखें

लाखों तीर्थयात्रियों के बीच अक्सर चप्पलें या जूते खो जाते हैं या इधर-उधर हो जाते हैं। इसलिए जहां उन्हें रखा है, उसे याद रखें और यदि संभव हो तो हल्के तथा आसानी से साफ किए जा सकने वाले अतिरिक्त जूते साथ रखें।

पूर्णता का भ्रम त्याग दें

जब लगभग बीस लाख थके हुए और त्रुटिपूर्ण मनुष्य एक ही समय और स्थान पर एकत्र होते हैं, तो कमियां और गलतियां होना स्वाभाविक है। इस यात्रा में पूर्णता का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ बिना किसी त्रुटि के संपन्न हो जाए, बल्कि यह है कि आप अपनी कमियों और भूलों को कितनी विनम्रता से स्वीकार करते हैं। मैं भी अपने साथ कुछ पछतावे लेकर लौटा—ऐसे क्षण जब मेरा ध्यान भटका या धैर्य जवाब दे गया। लेकिन इन्हीं कमियों में इस अनुभव का वास्तविक प्रकाश छिपा था।

यही वे सबक हैं जिन्हें मैं आज भी अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करता हूं और आने वाले आध्यात्मिक यात्रियों तक पहुंचाना चाहता हूं। हज के दौरान आपको अपने व्यवहार, अपने कर्मों और जरूरतमंदों के प्रति अपने रवैये पर विचार करने के अनगिनत अवसर मिलते हैं। उस समय आप स्वयं एक याचक बन जाते हैं, जो अपनी आत्मा की शुद्धि, मार्गदर्शन और दैवी कृपा की याचना करता है। यह यात्रा मनुष्य को अपनी प्रतिक्रियाओं, अपने स्वभाव और जीवन की चुनौतियों के प्रति अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने का अवसर देती है। अंततः इसका सबसे सरल और गहरा संदेश विनम्रता है—यह समझना कि इस संसार में हमें किस उद्देश्य से भेजा गया है: अल्लाह की सबसे शुद्ध और सच्ची उपासना करना। अल्लाह सभी हाजियों का हज स्वीकार फरमाए और उन पर अपनी अनंत रहमत और बरकतें नाजिल करे। आमीन।

लोकतंत्र बचाने की नयी लड़ाई

कांग्रेस की पूर्व सांसद और मध्यप्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार बनाई गईं मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करने के फैसले से भोपाल से लेकर दिल्ली तक हंगामा मचा है, जो लोकतंत्र बचाने के लिए जरूरी है और वक्त की मांग भी है। चार साल पहले चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जब तत्कालीन रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसीह ने मतपत्रों में गड़बड़ी कर भाजपा को जिताया था, तो सारा वाकया कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय तक ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया था। लेकिन सत्तारुढ़ भाजपा को न तब कोई फर्क पड़ा, न अब पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इसी बात का जश्न मना रहे हैं कि उन्हें सत्ता पर बैठे बारह साल पूरे हो गए। मीडिया भी इस समय भाजपा के जश्न की खबरों में गले तक डूबा हुआ है। इस देश का मीडिया जागरुक प्रहरी की भूमिका निभाता तो कल से लेकर इन पंक्तियों के लिखे जाने तक उन सवालों पर तीखी बहसें करवा रहा होता, जिन्हें कांग्रेस ने उठाया है। इसके बाद न चुनाव आयोग और न भाजपा का दुस्साहस इतना बढ़ता कि वे इस मामले में कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा करते। क्योंकि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव यही कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ही गलती की। वहीं इस मामले को कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान के नजरिए से भी देखा जा रहा है। हालांकि असल मुद्दा यह है कि भाजपा को जिताने के लिए कांग्रेस के साथ या कहें कि लोकतंत्र के साथ बेईमानी की गई है। गौरतलब है कि मीनाक्षी नटराजन का पर्चा 9 जून को रिटर्निंग अधिकारी ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि उन्होंने तेलंगाना में अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मामले का जिक्र नहीं किया। जबकि हकीकत यह है कि उन पर कोई मामला दर्ज नहीं हुआ, कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई, केवल निजी शिकायत मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ की गई है। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि किसी की निजी शिकायत पर अदालत से एक नोटिस आया, जिसमें सुश्री नटराजन से कहा गया कि आप आकर हमें बताइए कि हम केस का संज्ञान लें या नहीं। मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेना एक प्राथमिक चरण होता है और उसमें ये फैसला किया जाता है कि केस आगे चलना चाहिए या नहीं। बिना संज्ञान के कोई भी क्रिमिनल केस जन्म ही नहीं लेता है। ध्यान देने की बात ये है कि चुनाव आयोग के कानून में स्पष्ट लिखा है कि प्रत्याशी को सिर्फ वही खुलासा करना है, जिसमें अपराध अगर सिद्ध हो चुका हो और दो साल से ज्यादा की सजा हो। रिटर्निंग अधिकारी को यही देखना होता है। लेकिन इस मामले में मजिस्ट्रेट ने संज्ञान नहीं लिया है। तो आरोप पत्र दाखिल होना और आरोप तय होना बाद की बात है। लेकिन रिटर्निंग अधिकारी ने खुद ही तय कर लिया कि यह आपराधिक मामला है, जिसे मीनाक्षी नटराजन ने छिपाया और इस आधार पर उनका नामांकन रद्द कर दिया। देश की वरिष्ठ वकील तीस्ता सीतलवाड का भी कहना है कि 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33 ए के तहत ऐसी कोई जानकारी तभी दी जानी है जब अदालत आरोप तय कर दे। अदालत का नोटिस इस बात का सबूत है कि अभी तक आरोप तय नहीं किए गए हैं। जब तक आरोप तय नहीं हो जाते, तब तक जानकारी देने की जरूरत नहीं है। इसलिए रिटर्निंग अधिकारी ने गैर-कानूनी और नियम-विरुद्ध काम किया है। तीस्ता सीतलवाड ने कहा है कि उनके खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए और उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। हो सकता है कांग्रेस ऐसा करे और रिटर्निंग अधिकारी पर बाद में कार्रवाई हो। लेकिन क्या इससे चुनाव आयोग की जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं। भाजपा सत्ता पर बने रहने के लिए भले सौ तरह के छल-कपट करे, लेकिन यह तभी कामयाब होंगे, जब देश की संवैधानिक संस्थाएं भी इन कुटिल चालों की तरफ से आंखें मूंद ले। चुनाव आयोग इसी तरह नजरें बचाता दिख रहा है। मंगलवार शाम को जब पता चला कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज किया गया है, तो कांग्रेस नेताओं ने फौरन दिल्ली में केन्द्रीय निर्वाचन आयोग पहुंच कर शिकायत दर्ज कराना चाही। लेकिन उन्हें वहां किस तरह सुरक्षाकर्मियों ने रोका, इसे पूरे देश ने देखा और दुनिया भी देख ही रही होगी कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का निर्वाचन आयोग विपक्ष के सांसदों के साथ कैसा व्यवहार करता है। वहीं मध्यप्रदेश में कांग्रेस से चुनाव आयोग ने कहा कि 2 घंटे में वह जवाब देगा, लेकिन इन पंक्तियों के लिखे जाने तक कोई जवाब नहीं आया है। इस बीच कांग्रेसियों ने सामूहिक उपवास शुरू किया है। राज्य चुनाव आयोग के दफ्तर में संघ की यूनिफॉर्म लगा दी गई है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर अदालत जाने की तैयारी कर रही है, साथ ही राष्ट्रपति के पास भी शिकायत दर्ज की जाएगी। देश में सामान्य तौर पर जब भी राजनैतिक दल को कोई शिकायत होती है, तो इसी तरह के तरीके अपना कर इंसाफ की मांग उठाई जाती है। लेकिन भाजपा शासन में सामान्य तौर-तरीके की परिभाषा बदल चुकी है। अब हम एक ऐसे असामान्य, असाधारण और अभूतपूर्व शासन को देख रहे हैं, जिसके लिए लज्जा, निंदा, परिमार्जन जैसे शब्द अस्तित्व ही नहीं रखते हैं। लोकलाज की परवाह किए बगैर नरेन्द्र मोदी उस वक्त विदेश चले गए, जब उन्होंने देशवासियों से विदेश न जाने और तेल बचाने जैसी अपील की। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश समेत कई जजों के साथ केन्द्रीय कानून मंत्री और संसदीय कार्यमंत्री इन दिनों लंदन में बैडमिंटन मैच खेल रहे हैं, यह खर्च भी जनता ही उठा रही है। नीट पेपर लीक में कई छात्रों ने आत्महत्या कर ली, भ्रष्ट निर्माण के कारण लगी आग में दिल्ली में एक साथ 21 लोग जलकर मर गए, और शोकाकुल परिवारों को उनके हाल पर छोड़कर पूरा एनडीए कुनबा सत्ता की सालगिरह की खुशियां मना रहा है। सत्ता पर बैठे लोगों का ऐसा व्यवहार 2014 से पहले कभी नहीं देखा गया। लेकिन अब यही नया सामान्य है।

भू-माफिया अपने अवैध साम्राज्य को बचाने के लिए कर रहा है साजिश।

भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले चौथे स्तंभ के खिलाफ रच रहा है षड्यंत्र!

संयम भारत संवाददाता

व्यूरो,भदोही, ज्ञानपुर। जब शासन प्रशासन ने भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का बराबर निर्देश दे रहे हैं, तो फिर भू माफिया कमला शंकर मिश्रा को कौन संरक्षण दे रहा है? भू-माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने के कारण यह सवाल उठ रहा है कि क्या इस भू-माफिया को संरक्षण देने वाला शासन प्रशासन से भी अधिक प्रभावशाली हो गया है? भदोही जनपद ज्ञानपुर तहसील का भू-माफिया कमला शंकर मिश्रा के कानून विरोधी कारनामों की बहुत लंबी सूची है। इसने एक ही कैंपस में अलग-अलग नाम से चार विद्यालयों की मान्यता ले रखी है। इस फजीर्वाडे को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा इसके विरुद्ध इस मामले की जांच करके प्राथमिक की दर्ज कराए जाने की मांग की गई है। जांच करने पर पता चला है कि भू माफिया कमला शंकर मिश्रा जो कि जनपद के चर्चित माफिया सरगना के साथ मिलकर ज्ञानपुर तहसील में भोले वाले किसानों की एवं सरकारी जमीन को हड़प लिया है। गरीबों, किसानों, दलित के व सरकारी जमीनों के रिकॉर्ड में हेरा फेरी करके उनकी जमीन को अपने परिवार के नाम व अपने संस्था में दर्ज करवा करके उस पर कब्जा कर लिता है। इसने ग्राम समाज, पंचायत भवन, पी डब्लू डी, पावर हाउस सार्वजनिक जमीन,बच्चों के खेल के मैदान आदि की जमीनों पर कब्जा करके जमीन की फर्जी खसरा खतौनी इंद्राज करके इसने अपने पिता, भाई, और अपने परिवार के नाम दर्ज करवा दिया। बीसों बीघा जमीन पर अवैध कब्जा करने के बाद इसने इस जमीन पर एक बड़ा सा विद्यालय का भवन बनवाया और उस भवन में के पते पर चार-चार विद्यालयों की मान्यता ले रखी है। जबकि किसी भी विद्यालय के नाम से जमीन नहीं है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का यह कहना है कि यदि किसी विद्यालय के नाम से जमीन की रजिस्ट्री वाले कागज जब तक कार्यालय में नहीं जमा होते। उस विद्यालय को मान्यता नहीं दी जाती। लेकिन इस भू-माफिया ने एक ही कैंपस में अनेक कॉलेजों की मान्यता ले रखी है और किसी भी कॉलेज के नाम से जमीन की रजिस्ट्री का कागज इसने नहीं लगाया है। इस बिंदु पर अधिकारियों को संज्ञान में लेते हुए जांच करते हुए इस शिक्षा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लोगों का कहना है कि यह भू माफिया तो है ही। क्षेत्र का बहुत बड़ा शिक्षा माफिया भी है। यही नहीं इसमें ग्राम समाज की जो बची हुई जमीन है। उसको लूटने की योजना बना रखी है और जो भी सरकारी क्षेत्र की जमीन है। उन जमीनों पर कब्जा करने की फिराक में लगा है। सूत्रों का कहना है कि भू-माफिया शंकर मिश्रा ज्ञानपुर तहसील में जब तैनात था। तो तैनाती के दौरान इसने अपने गांव को ही अपना कार्य क्षेत्र बना दिया तथा हल्का लेखपाल के रूप में अपने गांव में ही तैनाती करा ली। जबकि लेखपाल जिस गांव का होता है। उस गांव में उसको तैनात नहीं किया जाता। लेखपाल के पद पर कार्य करते हुए परगना अधिकारी द्वारा इसको इसके ही गांव का कार्यभार कैसे दिया गया? इसकी अगर जांच कराई जाए तो पर एसडीएम की भी संदिग्ध भूमिका सामने आ सकती है तथा इसके सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे लेखपाल, कानूनगो के भ्रष्टाचार की वजह से पूरे ज्ञानपुर तहसील में हाहाकार मचा हुआ है। उसके खिलाफ बार-बार शिकायत किए जाने के बावजूद इन दोनों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होने से किसानों में भारी रोष व्याप्त है। लोगों ने जिलाधिकारी से इन दोनों को निलंबित करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान इसने ग्राम समाज पंचायत भवन बच्चों के खेल के मैदान सार्वजनिक जमीन आदि की जमीनों पर फजीर्वाड़ा करते हुए बीसों बीघा जमीन अपने भाइयों एवं परिवार के नाम से दर्ज करवा दी। गांव के ही दिव्यांग दलित मल्लू की जमीन पर इसने अवैध कब्जा कर लिया। उसकी जमीन पर कब्जा करने के लिए इसने फर्जी हलफनामा तैयार कराया और फिर मल्लू की जमीन पर इसने कब्जा करते हुए उसे बेघर कर दिया। उच्च अधिकारियों को शिकायत्री पत्र भेज भेज कर दलित मल्लू जो कि दोनों आंखों से दिव्यांग है। भगवान ने दलित मल्लू की आंखें छीन ली तो इस भू-माफिया ने उसकी जमीन छीन ली। इसकी जालिमाना हरकतें बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और जब से इसके विरुद्ध विभिन्न समाचार पत्रों में खबरों का प्रकाशन शुरू हुआ है। यह बौखला गया है। अब अपने माफियागर्दी वाले साम्राज्य को बचाने के लिए तरह-तरह की चाल चल रहा है। यह अपने माफिया साम्राज्य को बचाए रखने के लिए अब माफिया सरगना की मदद से शिकायतकताओं को डराने धमकाने में लगा है। जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में भारी रोष व्याप्त है। इस भू माफिया और उसके सहयोगी कानूनगो,लेखपाल आदि अब चौथे स्तंभ को अब दबाने तथा पत्रकारों को चुप करने की कोशिश में लगे हैं। इसके विरुद्ध जब से समाचारों का प्रकाशन शुरू हुआ है। जिलाधिकारी ने उसे बहुत ही गंभीरता से लिया है। शिक्षा विभाग के अधिकारी भी समाचारों को पढ़कर बहुत असहज है कि एक ही कैंपस के नाम पर कैसे चार-चार विद्यालय चल रहे हैं। कब्जा की गई जमीन के बारे में पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई शुरू हो गई है। स्थानीय पुलिस सूचना इकाई के द्वारा इसके बारे में सूचना एकत्र कराई जा रही हैं। लोगों का यह भी कहना है कि ईडी और सीबीआई के द्वारा इसके काले कारनामों की जांच कराई जाए तो बहुत बड़े माफिया रैकेट का भंडाफोड़ हो सकता है। काले धन के द्वारा इसलिए बहुत बड़ा अपना साम्राज्य खड़ा कर रखा है और रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार के जरिए जो उसने अवैध कमाई की है। उसी के बल पर अपने खिलाफ होने वाली शिकायतों पर लीपापोती करवा देता है। लेकिन इस बार जिला प्रशासन ने बहुत सख्त रवैया इस भूमिया के कब्जे से ग्राम समाज ग्राम पंचायत बच्चों के खेल के मैदान, पावर हाउस सार्वजनिक आदि की जमीन खाली कराई जाए और भू-माफिया ने जो अपने कार्यकाल के दौरान लोगों की जमीनों को कब्जा किया उसके अवैध कब्जे को हटाया जाए।

लखनऊ विश्वविद्यालय में एक और छात्र का निष्कासन, छात्रों का 10वें दिन भी धरना जारी

लखनऊ (संवाददाता)। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक और छात्र को अनुशासनहीनता के आरोपों के चलते निष्कासित कर दिया है। बीएएलएलबी के सेकेंड ईयर स्टूडेंट सत्यम यादव पर यह कार्रवाई की गई है। सत्यम को लखनऊ विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध किसी भी महाविद्यालय में भविष्य में प्रवेश न देने का आदेश जारी किया गया है। वहीं, एलयू कैंपस में निष्कासन के विरोध में सरस्वती प्रतिमा के पास धरने पर बैठे छात्रों का प्रदर्शन लगातार दसवें दिन भी जारी है। धरने पर बैठे छात्रों के समर्थन में पूर्व छात्रसंघ के पदाधिकारियों के अलावा सपा और कांग्रेस सरीखे कई विपक्षी दलों से जुड़े लोगों के आने का सिलसिला जारी है। कई सामाजिक कार्यकताओं ने भी छात्रों के पक्ष में खुलकर आवाज बुलंद की है। इस बीच पूर्व सांसद धनंजय सिंह का भी छात्रों के समर्थन का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में धनंजय सिंह छात्रों के

फीस वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन करने की बात कही है। इसी बीच गुरुवार को कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल विश्वविद्यालय पहुंचा और कुलसचिव डॉ. भावना मिश्रा से मुलाकात कर मामले में हस्तक्षेप की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने छात्र नेताओं के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई वापस लेने और बढ़ी हुई फीस पर पुनर्विचार करने की मांग उठाई। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने कुलसचिव से कहा कि छात्र प्रतिनिधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई और फीस वृद्धि के फैसले से छात्रों में व्यापक असंतोष है। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन को सकारात्मक पहल करते हुए दोनों मुद्दों की समीक्षा करनी चाहिए, ताकि शैक्षणिक माहौल प्रभावित न हो। प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि संवाद के माध्यम से विवाद का समाधान निकाला जाना चाहिए और छात्रों की जायज मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। कुलसचिव से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में पूर्व विधायक श्याम किशोर शुक्ला, सुरेंद्र यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं प्रवक्ता अंशु अवस्थी, कुलदीप दिवाकर, संजय सिंह, अंकित तिवारी, अमित राय, श्रवण गुप्ता, अब्दुल्ला आजम, आर्यन मिश्रा और शमी खान शामिल रहे।

हनुमान मंदिर के सामने चौड़ी होगी सड़क, पीडब्ल्यूडी ने 10 दुकानें गिराई

लखनऊ (संवाददाता)। राजधानी के अलीगंज स्थित नया हनुमान मंदिर के सामने वर्षों से लगने वाले जाम से राहत दिलाने के लिए सड़क चैड़ीकरण का काम शुरू हो गया है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्लयूडी) ने गुरुवार को अभियान

चलाकर सड़क किनारे बनी 10 दुकानों को ध्वस्त कर दिया। छह दुकानों को हटाने के लिए शुक्रवार को फिर कार्रवाई की जाएगी। अलीगंज के प्राचीन हनुमान मंदिर में विशेष रूप से जेठ माह के बड़े मंगल पर लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मंदिर के आसपास करीब 250 मीटर का हिस्सा लंबे समय से यातायात की सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। मंदिर से पहले सड़क फोरलेन है, लेकिन मंदिर के सामने पहुंचते ही सड़क संकरी हो जाती है, जिससे रोजाना जाम लगता है। बड़े मंगल और अन्य धार्मिक आयोजनों के दौरान स्थिति और गंभीर हो जाती है। पीडब्लयूडी की योजना के तहत मंदिर के सामने वाली पट्टी पर सड़क को करीब 10 मीटर तक चैड़ा किया जाना है।

ब्यूटी पार्लर में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने बचाई दो लोगों की जान

लखनऊ (संवाददाता)। ब्यूटी पार्लर में शार्ट सर्किट से लगी आग में दो लोग

फंस गए जिन्हें फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू कर बचा लिया। गौतमपल्ली थाना क्षेत्र की क्रिश्चियन कालोनी में गुरुवार सुबह एक मकान में संचालित ब्यूटी पार्लर में आग लग गई।आग की लपट व धुएं के बीच दो लोग फंस गए। चीख पुकार सुनकर पड़ोसियों ने दमकल को सूचना दी। आग की सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और बचाव अभियान चलाकर छत पर धुएं से घिरे दो लोगों को सीढ़ी की मदद से सुरक्षित नीचे उतार लिया। आग लगने के समय दो लोग भवन के अंदर फंस गए थे। दमकल कर्मियों ने दोनों को लोहे की सीढ़ी के माध्यम से सुरक्षित बाहर निकाल लिया।बाद मशक्कत दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। गौतमपल्ली की क्रिश्चियन कॉलोनी में इजस्ट फॉर डिवाइसश केडीए ब्यूटी पार्लर में आग लगने की प्रारंभिक जांच में कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। कोई जनहानि नहीं हुई, पार्लर का सामान जलकर नष्ट हो गया। मकान मालिक के मुताबिक आग भूतल पर संचालित पार्लर में लगी थी। पार्लर की संचालिका दीपिका राठौड़ हैं। आग से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन पार्लर में रखा सामान जल गया।

राजनीति में मतभेद स्वीकार है, बेटियों का अपमान नहीं, सपा मुख्यालय के बाहर लगा होर्डिंग

लखनऊ (संवाददाता)। राजधानी में समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर लगाए गए एक बड़े पोस्टर ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। पोस्टर में बेटियों के सम्मान और महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए गए हैं। पोस्टर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ लिखा गया है, राजनीति में मतभेद स्वीकार है, बेटियों का अपमान नहीं। पोस्टर में यह भी लिखा गया है कि बेटियों का सम्मान, देश की पहचान और सवाल उठाया गया है कि जब एक बेटी की इज्जत पर हमला हुआ तो कानून का बुलडोजर कार्रवाई करने में लाचार क्यों दिखाई दिया? समाजवादी पार्टी से जुड़े नेताओं का कहना है कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन महिलाओं और बेटियों के सम्मान के साथ किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। पोस्टर के जरिए महिला सुरक्षा और कानून-

व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि हाल के घटनाक्रमों को लेकर विपक्ष महिला सम्मान के मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहा है और इसी कड़ी में यह पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर लगाने वाले सपा नेता मो. इखलाक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ नारी शक्ति और महिला सम्मान का नारा देती है, लेकिन दूसरी तरफ उसके ही लोग महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बहू-बेटियों की सुरक्षा और सम्मान की बात करने वाली पार्टी के लोगों द्वारा किसी बेटी के चरित्र का हनन किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति में नारी को देवी का स्वरूप माना जाता है और उसकी पूजा की जाती है। ऐसे में किसी भी बेटी या महिला के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। मो. इखलाक ने कहा कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन बहू-बेटियों का सम्मान उससे कहीं ऊपर है। राजनीतिक विरोध के नाम पर महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाना न सिर्फ गलत है, बल्कि सामाजिक मूल्यों के भी खिलाफ है। उन्होंने कहा कि बेटियों के सम्मान के साथ राजनीति नहीं की जानी चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को इस विषय पर संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। सपा नेता ने मांग की कि महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि समाज में एक स्पष्ट संदेश जाए।

अखंड आर्यावर्त आर्य त्रिदंडी महासभा इको गार्डन पर कॉकरोच पार्टी का करेगी पुतला दहन

लखनऊ (संवाददाता)। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपते पहली बार राजधानी लखनऊ में आ रहे हैं। उनका उद्देश्य नीत परीक्षा पेपर लीक मामले में विरोध करना है। एक वीडियो जारी करके उन्होंने बताया कि शुक्रवार दोपहर 12.00 बजे इको गार्डन पर उनका विरोध प्रदर्शन होगा जिसमैं बड़ी संख्या में कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य तथा स्टूडेंट शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार उनके सपोर्ट में कई राजनीतिक पार्टियों भी शामिल है। वही सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अखंड आर्यावर्त आर्य त्रिदंडी महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष गौरव गोस्वामी ने उनके विरोध प्रदर्शन के विरोध में दोपहर 12:00 बजे इको गार्डन में अभिजीत दीपते के प्रदर्शन के विरोध में उनके ही सामने उनका पुतला दहन का ऐलान किया है।

सपा-कांग्रेस मिलकर लड़ेगी असेम्बली इलेक्शन

- मिशन 2027: लक्ष्य फतह और सूबे में हुकूमत
- कांग्रेस जहां मजबूत वहीं मिलेगा कांग्रेसी को टिकट
- टिकट बंटवारे पर मंथन और 200 नाम तय

लखनऊ (संवाददाता)। समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा की चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। सपा यूपी में कांग्रेस से गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेगी। मिशन 2027 का लक्ष्य फतह और सूबे में सरकार है। दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर फामूर्ला लगभग तय हो गया। टिकट नही सिर्फ जीत पर फोकस है। जीत की गारंटी वाली सीटें ही एक-दूसरे के खाते में जाएंगी। कांग्रेस का जनाधार जहां होगा सपा वो सीट छोड़ेगी। सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं, बताना होगा कि पिछले चुनावों में कितना वोट मिला था व जातीय समीकरण के हिसाब से उम्मीदवारी कितनी मजबूत है। 200 सीटों पर प्रत्याशियों का नाम भी तय हो गया है। चुनाव की घोषणा से पहले उम्मीदवारी तय कर दी जाएगी, जिससे क्षेत्र में काम करने का पूरा मौका मिले। टिकट बंटवारे को लेकर सम्भावित मनमुटाव भी कम होगा। ऐन वक्त पर टिकट से उम्मीदवार को तैयारी का मौका कम मिलता है और चुनाव के दौरान नाराजगी का असर दिखाई पड़ता है। सपा नहीं चाहती है कि 2027 के चुनाव मे भितरघात हो। नाराजगी नहीं तो पार्टी नेता मिलकर तैयारी करेंगे और परिणाम बेहतर होगा।सपा नेतृत्व हर जिले की विधानसभावार सीटों पर चर्चा कर रहा है। सपा मुखिया स्वयं ध्यान दे रहे हैं। फीडबैक लेने के लिए जिलाध्यक्ष और नगर कार्यकारिणी के लोगों को बुलाया जा रहा है। 200 सीटों पर संभावित उम्मीदवारों की पहचान हो चुकी है। जुलाई के पहले हफ्ते तक उम्मीदवारों की शार्टलिस्टिंग होगी। उम्मीदवारों के बारे में खुफिया तरीके से पड़ताल कराई जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि क्षेत्र में उसकी क्या पोजीशन है।सपा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितने टिकट देगी, अभी तय नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि उसके हिस्से में वही सीटें जाएंगी जहां मजबूत होगी। कांग्रेस को सीटवार बताना होगा कि वह कहां- कहां मजबूत है।जहां कांग्रेस की सीट निकलती दिखेगी टिकट मिलना तय है।

संत की हत्या मामले में बुलडोजर एक्शन

- ढहाया अतीक का घर ,कई अरेस्ट
- अजान के वक्त भजन बजाने पर ली थी पुजारी की जान

लखनऊ (संवाददाता)। उन्नाव जिले का सनसनीखेज मामला सामने आया है।उन्नाव के बांगरमऊ इलाके में मस्जिद के पास मंदिर बना रहे 45 वर्षीय संत मिलन दास की दिनदहाड़े चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। अजान के समय लाउडस्पीकर पर भजन बजाने को लेकर हुए विवाद के बाद वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपित सभासद अतीक के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। अतीक के अहाते में हत्या हुई थी। खौफनाक वारदात 9 जून दोपहर को हुई। संत मिलन दास अपने घर से कुछ दूरी पर स्थित सभासद अतीक के अहाते में बैठे थे। जैसे ही उठकर जाने लगे, हमलावरों ने उनपर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमलावरों ने आसपास के लोगों को भी चाकू दिखाकर डराया और वहाँ से भाग निकले। संत को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।संत मिलन दास के परिजनों के मुताबिक वह मुस्लिम बहुल इलाके में अपनी जमीन पर मंदिर का निर्माण करवा रहे थे। मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर एक मस्जिद भी है। आरोपित संत द्वारा मंदिर बनवाने और वहाँ भजन बजाने से काफी समय से खुन्नस खाए हुए थे। इससे पहले भी साल 2013 और 2023 में संत मिलन दास पर हमले हो चुके थे। वारदात से आक्रोशित लोगों ने बांगरमऊ-हरदोई मार्ग जाम कर दिया। पुलिस ने भारी बल तैनात किया। पुलिस ने इसराइल, लल्ली, यामीन, शानू और शफी समेत 8 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। तीन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य आरोपित अतीक के घर पर बुलडोजर एक्शन भी लिया है।

संक्षिप्त समाचार

कैफे अकासा ने योग दिवस पर विशेष भोजन का चैथा संस्करण लॉन्च किया

लखनऊ (संवाददाता)। अकासा एयर की ऑनबोर्ड भोजन सेवा, कैफे अकासा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए अपने योग दिवस विशेष भोजन का चैथा संस्करण लॉन्च किया है। वेलनेस, संतुलन और सचेत जीवन के सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करने के लिए सोच-समझकर तैयार किया गया यह विशेष भोजन, उड़ान के दौरान एक पौष्टिक अनुभव प्रदान करने के लिए स्वास्थ्यवर्धक सामग्रियों को ताजा स्वादों के साथ जोड़ता है। योग दिवस विशेष भोजन में एवोकाडो, अनार और तुलसी के साथ ताजा मिलेट सलाद शामिल है, जिसे बेरी म्यूसली योगर्ट पार्फे के साथ जोड़ा गया है और पसंदीदा पेय के साथ परोसा जाता है। पोषक तत्वों से भरपूर मिलेट, ताजे फलों, दही और मौसमी सामग्रियों के गुणों को एक साथ लाते हुए, यह भोजन यात्रियों को एक हल्का लेकिन संतोषजनक विकल्प देने के लिए डिजाइन किया गया है जो स्वाद से समझौता किए बिना सचेत खान-पान का उत्सव मनाता है। यह विशेष भोजन जून 2026 के पूरे महीने अकासा एयर नेटवर्क पर उपलब्ध रहेगा, और इसे अकासा एयर की वेबसाइट तथा मोबाइल ऐप पर आसानी से प्री-बुक किया जा सकता है। चूंकि योग दुनिया भर में स्वस्थ जीवन शैली और सचेत विकल्पों को प्रेरित कर रहा है, इसलिए यह विशेष रूप से तैयार की गई पेशकश यात्रियों को यात्रा के दौरान भी वेलनेस को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करके इस अवसर की भावना को जीवंत करती है। मिलेट का समावेश, जो अपने पोषण संबंधी मूल्य और भारतीय खाद्य परंपराओं से गहरे जुड़ाव के लिए जाना जाता है, स्वास्थ्यवर्धक, संतुलित भोजन के लिए बढ़ती पसंद को दशार्ता है जो शरीर और मन दोनों को पोषण देता है। अब अपने चैथे वर्ष में, योग दिवस विशेष भोजन सोच-समझकर तैयार किए गए पाक अनुभवों के माध्यम से सांस्कृतिक और मौसमी अवसरों को मनाने की कैफे अकासा की परंपरा को जारी रखता है। अगस्त 2022 में परिचालन शुरू करने के बाद से, अकासा एयर विभिन्न उत्सवों से जुड़ी क्षेत्रीय विशेषताओं को दशार्ने वाले विशेष रूप से तैयार किए गए भोजन विकल्प प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रही है। मकर संक्रांति से लेकर वेलेंटाइन डे, होली, ईद, ईस्टर, मदर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, नवरोज, ओणम, गणेश चतुर्थी, दशहरा, दिवाली, बाल दिवस और क्रिसमस तक, कैफे अकासा उत्सव के व्यंजनों के साथ उड़ान के अनुभव को बेहतर बनाना जारी रखे हुए है। एयरलाइन अपने नियमित मेनू पर केक का प्री-सिलेक्शन विकल्प भी देती है, उन यात्रियों के लिए जो आसमान में अपने प्रियजनों के साथ विशेष अवसर मनाना चाहते हैं। कैफे अकासा का बार-बार अपडेट होने वाला मेनू सोच-समझकर तैयार किया गया है ताकि इसमें विभिन्न प्रकार के गॉरमेट मील्स, स्नैक्स और ताजा पेय शामिल हों, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि यह व्यापक आहार और पाक प्राथमिकताओं को पूरा करता है। मेनू में 45 से अधिक भोजन विकल्प मिलते हैं, जिसमें फ्यूजन मील, क्षेत्रीय ट्विस्ट के साथ ऐपेटाइजर और स्वादिष्ट डेसर्ट शामिल हैं, जिन्हें पूरे भारत के प्रतिष्ठित शेफ द्वारा विशेष रूप से तैयार किया गया है।

यूपी के मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में बनेंगे धर्मांतरण रोकथाम सेल, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का सख्त निर्देश

लखनऊ (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्य के सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में धार्मिक परिवर्तन रोकथाम सेल (धर्मांतरण रोकथाम सेल) बनाने के निर्देश दिए हैं। यह कदम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक रेजिडेंट डॉक्टर से जुड़े धर्मांतरण मामले और संजय गांधी पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एक कर्मचारी की बेटी के लापता होने की घटना के बाद उठाया गया है। आदेश के बाद अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अपने सभी संबद्ध मेडिकल और डेंटल संस्थानों को तुरंत ऐसे सेल बनाने के निर्देश जारी किए हैं। निदेर्शों के अनुसार, इन धर्मांतरण रोकथाम सेल का काम छात्रों, रेजिडेंट डॉक्टरों, फैकल्टी और अन्य कर्मचारियों को संबंधित कानूनों और संस्थागत जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करना होगा। इसके अलावा इन सेल को संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और किसी भी शिकायत को उचित तरीके से जांच के लिए आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। संस्थानों को जागरूकता अभियान और शैक्षणिक कार्यक्रम चलाने के लिए भी कहा गया है, ताकि छात्र और कर्मचारी कानून, अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी रख सकें। सभी संबद्ध मेडिकल और डेंटल कॉलेजों को जल्द से जल्द ये सेल बनाने और इसकी अनुपालन रिपोर्ट विश्वविद्यालय को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, इन सेल में आने वाली किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई के लिए व्यवस्था बनाने को भी कहा गया है। केजीएमयू धर्मांतरण मामला एक पूर्व जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर पर लगे आरोपों से जुड़ा है, जिसमें कहा गया है कि उसने महिला सहकर्मियों का शोषण कर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया। इस मामले की जांच एसटीएफ कर रही है और मेडिकल कैंपसों में निगरानी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा एसजीपीजीआईएमएस की 21 वर्षीय युवती 21 मई से लापता है। परिवार ने एक व्यक्ति इरशाद अली पर अपहरण का आरोप लगाया है और दावा किया है कि उसने पीछा किया, ब्लैकमेल किया और हो सकता है कि उसे देश से बाहर ले जाया गया। इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस पहल का समर्थन किया है और कहा है कि इस्लाम जबरन धर्म परिवर्तन की अनुमति नहीं देता, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि किसी भी मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि राज्यपाल के ऐसे कदम से कोई आपत्ति नहीं है और जबरन धर्म परिवर्तन किसी भी धर्म में स्वीकार्य नहीं है।

विधानसभा चुनाव में अभी देर, सियासी पार्टियों की तैयारी में नही

- बीजेपी का बड़ा दांव, तीन तलाक पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को घर, बीमा और रोजगार से जोड़ने की तैयारी
- विकास को चुनावी मुद्दा बनायेगी बीजेपी

लखनऊ (संवाददाता)। विधानसभा चुनाव में अभी भले ही देर है लेकिन सियासी पार्टियों की तैयारी में नही।सत्ताधारी ही नही विपक्षी दलों ने भी अभी से गुणाभाग शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आते ही सियासी दल अपने-अपने तरीके से मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी विकास और कल्याणकारी योजनाओं को उपलब्धि बता रही है तो विपक्ष इन दावों को चुनावी रणनीति करार दे रहा है।2027 में होने वाले असेम्बली चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी ने मुस्लिम समुदाय के लिए भी नई कल्याणकारी योजनाओं पर जोर देना शुरू कर दिया है।योगी सरकार का उद्देश्य दिखाना है कि विकास, जनकल्याण की योजनाओं का लाभ हर वर्ग को मिल रहा है। तीन तलाक पीड़ित महिलाओं को विशेष सुविधाएं देने की योजना खासी चर्चा में है।सूबाई सरकार तीन तलाक से प्रभावित महिलाओं को आवास और स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मुताबिक महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास है। इन्हें कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा।बीजेपी का दावा है कि योजनाएं किसी धर्म या समुदाय के आधार पर नहीं बल्कि जरूरत के आधार पर लागू की जाती है। पार्टी मुस्लिम समुदाय को संदेश देना चाहती है कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर नागरिक को समान रूप से मिल रहा है।विपक्षी दलों ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं।सपा का कहना है कि तमाम लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं सरकार को योजनाओं की घोषणा के बजाय महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसी समस्याओं पर काम करना चाहिए।

अधिवक्ता गौरव कुमार हाईकोर्ट में जिला पंचायत कौशांबी के वादों की करेंगे पैरवी

संयम भारत संवाददाता

व्यूरो,कौशांबी जिला पंचायत कौशांबी की ओर से पत्र जारी करके बताया गया कि अधिवक्ता गौरव कुमार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में वादों की पैरवी के

लिए अधिवक्ता नियुक्त किया है। अध्यक्ष ने पत्र जारी करके बताया है कि अधिवक्ता गौरव कुमार के नियुक्ति से जिला पंचायत कौशांबी को बल मिलेगा। गौरव के नियुक्ति पर तमाम अधिवक्ताओं ने खुशी जताई है।

विधवा पेंशन में फजीर्वाड़े की आशंका, 1.05 लाख महिलाओं का सत्यापन कराने में जुटा विभाग

संवाददाता

प्रयागराज। विभाग को आशंका है कि कुछ मामलों में गलत दस्तावेजों के आधार पर योजना का लाभ लिया जा रहा है। इस कारण लाभार्थियों के अभिलेखों और उनकी वास्तविक स्थिति तक की पड़ताल की जा रही है। महिला व बाल विकास विभाग की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर निराश्रित महिलाओं को एक हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। यह धनराशि वर्ष में चार किस्तों के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए पति का मृत्यु प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र समेत अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होता है। हाल के दिनों में प्राप्त नए आवेदनों और कुछ शिकायतों की जांच के दौरान विभाग को अनियमितताओं की आशंका हुई। इसके बाद जिले में योजना से जुड़ी सभी लाभार्थियों का सत्यापन शुरू कराया गया है। कई मामलों में स्थानीय स्तर पर भी जानकारी जुटाई जा रही है। जिला प्रोबेशन अधिकारी सर्वजीत सिंह ने बताया कि प्रयागराज जिले में वर्तमान समय में लगभग 1.05 लाख महिलाएं निराश्रित महिला पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं। सभी नए आवेदनों और संदिग्ध मामलों का नियमित सत्यापन कराया जा रहा है। हालांकि अभी तक फजीर्वाड़ा का एक भी मामला पकड़ में नहीं आया है।

प्रयागराज मंडल के 29 स्टेशनों पर बुकिंग एजेंट बेचेंगे टिकट

संवाददाता

प्रयागराज। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल ने 29 स्टेशनों पर टिकट बेचने की जिम्मेदारी स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट को देने की तैयारी की है। मंडल के स्टेशनों पर जल्द ही यह एजेंट तैनात हो जाएंगे। स्टेशनों पर चयनितों की नियुक्ति पूरी तरह संविदा और प्रति टिकट कमीशन के आधार पर होगी। एजेंट बनने के इच्छुक युवा 15 जुलाई तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। 20 मई 2027 तक के लिए अभी यह योजना है। बाद में इसका विस्तार किया जा सकता है। प्रयागराज मंडल के करछना, गोविंदपुरी, मानिकपुर, कानपुर अनवरगंज, जिवनाथपुर, कैलहट, डगमगपुर, बिरोही, मनोहरगंज, शुजातपुर, कटोधन, प्रेमपुर, बिदनपुर, कुरस्ती कला आदि स्टेशनों पर स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट की तैनाती होगी। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित एजेंट सभी शिफ्टों में कंप्यूटर के जरिये यात्रियों को अनारक्षित (जनरल) टिकट काउंटर से मुहैया कराएंगे।

सीनियर डॉक्टरों ने संभाली ओपीडी, देखे 1623 मरीज

संवाददाता

प्रयागराज। दोपहर में सिटी मजिस्ट्रेट विनय कुमार सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एके तिवारी व मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. एके वर्मा जूनियर डॉक्टरों से वार्ता के लिए पहुंचे। उन्होंने बताया कि जूनियर रेजिडेंट डॉ. मोसिन अली अपने घर पहुंच गए हैं। इस पर कुछ डॉक्टरों ने फोन लगाकर डॉ. मोसिन अली व उनकी बहन से बात की। इसके बाद जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ले ली। हड़ताल की वजह से रोजाना की तुलना में 50 फीसदी मरीज कम पहुंचे। दोपहर 12 से दो बजे तक कुल 23 मरीज भर्ती हुए। ओपीडी में पहुंचने वालों में नए की अपेक्षा फॉलोअप वाले मरीजों की संख्या अधिक रही। फिलहाल मेडिसिन, आथोर्पेडिक, ईएनटी, त्वचा रोग, हृदय रोग, दंत रोग, नेत्र रोग, गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग व स्त्री रोग की ओपीडी चलने से मरीजों ने राहत की सांस ली। पीएमएसएसवाई बिल्डिंग में भी सामान्य दिनों की तरफ किडनी रोग, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी सहित अन्य विभागों ने चिकित्सकों ने मरीजों को देखा। बृहस्पतिवार से एसआरएन अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। मरीजों की तकलीफ को देखते हुए सीनियर डॉक्टरों ने ओपीडी चलाई। सामान्य दिनों की तरह सुबह नौ से दोपहर दो बजे तक ओपीडी संचालित की गई। जूनियर डॉक्टरों ने भी हड़ताल वापस ले ली है। बृहस्पतिवार से स्वास्थ्य सेवाएं सुचारु चलेंगी।

जागृति शुक्ला की मौत के मामले में कार्यकारिणी सदस्यों ने दिया इस्तीफा

संवाददाता

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी सदस्य अंजली सिंह तोमर और कार्यकारिणी सदस्य व अनुशासनिक समिति के सदस्य आदित्य धर द्विवेदी ने स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल प्रकरण और महिला अधिवक्ता जागृति शुक्ला की मृत्यु के मामले में अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। अंजली सिंह तोमर ने अपने त्यागपत्र में कहा है कि एसआरएन अस्पताल प्रकरण में बार एसोसिएशन की ओर से अपनाए गए रवैये से वह अत्यंत निराश व क्षुब्ध हैं। अधिवक्ता हितों की प्रभावी व सम्मानजनक रक्षा किए जाने के स्थान पर जिस प्रकार मामले को संभाला गया। उससे संगठन की कार्यप्रणाली व नेतृत्व के प्रति उनका विश्वास प्रभावित हुआ है। आदित्य धर द्विवेदी ने बताया 20 मई को एसआरएन अस्पताल विवाद में बार एसोसिएशन का रवैया ढुलमुल रहा। इस कारण उन्होंने कार्यकारिणी सदस्य और अनुशासनिक समिति के सदस्य पद से त्यागपत्र दे दिया है।

तीसरे दिन भी जबरन डिस्चार्ज किए गए मरीज, खाली हुआ अस्पताल

संवाददाता

प्रयागराज। हनुमानगंज निवासी शीतल केसरवानी को पैरों में सूजन, सुस्ती व नसों में दर्द के चलते छह दिन पहले एसआरएन अस्पताल में भर्ती किया गया। इलाज पूरा होने से पहले ही बुधवार को दबाव बनाकर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। यह कोई एक मरीज की नहीं, बल्कि भर्ती सभी मरीजों की समस्या रही। हड़ताल की वजह से ट्रॉमा ट्रायज, इमरजेंसी मेडिसिन, सर्जरी, सात व 10 नंबर वार्ड में भर्ती मरीजों को जबरन डिस्चार्ज कर दिया गया। सर्जरी के पुरुष वार्ड में दरवाजे पर कुंडी लगा दी गई। दोपहर 12 बजे तक सभी वार्डों में सन्नाटा पसर गया। तीन दिन में 150 से ज्यादा मरीजों के ऑपरेशन टाल दिए गए। कब होंगे यह बताया नहीं गया। कुछ मरीज इलाज के अभाव में मरीज को रेफर कराकर चले गए। ऐसे में पुरानी बिल्डिंग के वार्ड सात और 10 के 25-25 बेड, न्यूरो सर्जरी विभाग के 21 बेड व पुरुष सर्जरी वार्ड के सभी 30 बेड खाली रहे।

12 वर्षों में शिक्षा, नवाचार, डिजिटल एवं कौशल विकास में अभूतपूर्व उपलब्धि - प्रोफेसर सत्यकाम

प्रधानमंत्री मोदी के ऐतिहासिक 12 वर्ष पूर्ण होने पर मुविवि में व्याख्यानमाला

संयम भारत संवाददाता

व्यूरो,उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज के सरस्वती परिसर स्थित तिलक शास्त्रार्थ सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा, सुशासन एवं राष्ट्र निर्माण के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन के निदेशानुसार व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया विश्वविद्यालय में दिनांक 11 जून से 21 जून, 2026 तक विभिन्न शैक्षिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक एवं जन-जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन एक विशेष पर्व के रूप में किया जा रहा है। । इस श्रृंखला में कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने "राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 : शिक्षा जगत का एक क्रांतिकारी उद्घोष" विषय पर प्रथम व्याख्यान देते हुए कहा कि विगत 12 वर्षों में भारत ने शिक्षा, प्रौद्योगिकी, नवाचार, डिजिटल सशक्तिकरण, कौशल विकास एवं आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भारत की शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करने का एक दूरदर्शी दस्तावेज है, जो विद्यार्थियों में ज्ञान, कौशल, नवाचार, अनुसंधान एवं नैतिक मूल्यों का समन्वित विकास सुनिश्चित करती है। कुलपति ने डिजिटल इंडिया अभियान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, डिजिटल शिक्षण, ई-कंटेंट निर्माण, ऑनलाइन शिक्षा तथा तकनीक आधारित अधिगम के बढ़ते महत्व पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज भारत ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से अग्रसर है तथा शिक्षा संस्थानों की भूमिका इस परिवर्तन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली की उपयोगिता को रेखांकित करते हुए कहा कि उच्च शिक्षा के प्रसार तथा सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि के लिए मुक्त विश्वविद्यालयों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रभावी है। उन्होंने कहा कि "विकसित भारत-2047" के संकल्प को साकार करने में शिक्षा जगत की केंद्रीय भूमिका है। प्रत्येक शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी एवं नागरिक राष्ट्र निर्माण की इस महान यात्रा का सहभागी है। उन्होंने "मैं नहीं, हम" की भावना को विकसित भारत के निर्माण का मूल आधार बताते हुए कहा कि सामूहिक प्रयास, सहयोग, सहभागिता एवं सकारात्मक सोच से ही एक सशक्त राष्ट्र, सुदृढ़ समाज एवं उत्कृष्ट संस्थाओं का निर्माण संभव है। कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने उपस्थित जनसमुदाय का आह्वान किया कि वे शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा राष्ट्रहित के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और अधिक सशक्त बनाएं तथा "दिव्य भारत, भव्य भारत" एवं "विकसित भारत-2047" के राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने में सक्रिय योगदान दें। नोडल अधिकारी प्रोफेसर संजय सिंह ने प्रारंभ में कुलपति, कुलसचिव एवं वित्त अधिकारी का स्वागत करते हुए विगत 12 वर्षों में प्रधानमंत्री के विराट कृत्यों को रेखांकित करते हुए दिव्य भारत भव्य भारत की रूपरेखा प्रस्तुत की। संचालन डॉ सुनील कुमार एवं धन्यवाद ज्ञापन कुलसचिव कर्नल विनय कुमार ने किया। जनसंपर्क अधिकारी डॉ प्रभात चन्द्र मिश्र ने बताया कि कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने राष्ट्र निर्माण, शिक्षा के उन्नयन तथा सामाजिक विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए आगामी 21 जून, 2026 तक आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता का संकल्प लिया। सम्पूर्ण वातावरण राष्ट्र भक्ति, प्रेरणा, सकारात्मक ऊर्जा एवं विकासोन्मुख चिंतन से ओत-प्रोत रहा। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के समस्त विद्याशाखाओं के निदेशकगण, अधिकारीगण, शिक्षकगण, कर्मचारीगण, शोधार्थी एवं विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

जरूरी मुददों पर जनता का ध्यान भटकाने में जुटी हुई है भाजपा- मोना

कांग्रेस विधानमण्डल दल की नेता ने पेपरलीक, मंहगाई व विद्युत आपूर्ति को लेकर सरकार की असफलता पर बोला हमला

संयम भारत संवाददाता

व्यूरो,लालगंज, प्रतापगढ़। क्षेत्रीय विधायक एवं कांग्रेस विधानमण्डल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने गुरूवार को एक दिवसीय दौरे मे यहां पार्टी कार्यकताओं के साथ संगठन सृजन अभियान की समीक्षा की। कार्यकर्ता बैठक में उन्होने कहा कि भाजपा की केन्द्र एवं राज्य सरकारें जनता की मूलभूत समस्याओ के निस्तारण को तरजीह देने की जगह मुददो को भटकाव दे रही है। उन्होने कहा कि नीट पेपरलीक को लेकर मध्य प्रदेश की छात्रा आकांक्षा चतुवेदी और महाराष्ट्र की मैथिली सोनवाने की आत्महत्या की घटनाओं के बाद मोदी सरकार की परीक्षा प्रणाली पर देश भर में गंभीर सवाल उत्पन्न हुआ है। उन्होने कहा कि पेपरलीक से मुंह चुरा रही भाजपा इसके सीधे जिम्मेदार

देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तक नहीं ले पायी। सीएलपी नेता आराधना मिश्रा ने कार्यकताओं से कहा कि भाजपा के सत्ता में बने रहने के अलोकतांत्रिक दांव से सतर्क और सावधान रहना होगा। उन्होने कहा कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का जबरिया नामांकन रदद होना भाजपा की सीट चोरी को उजागर कर गया है। उन्होने कहा कि महिला आरक्षण का शोर मचा रही भाजपा ने वहां विधायको की पर्याप्त संख्या न होने के बावजूद भी तीसरे उम्मीदवार को अलोकतांत्रिक ढंग से संसद में भेजने का हथकण्डा अपनाया है। कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि रसोई गैस सिलेण्डर को मंहगा कर भाजपा ने गरीब और मध्यम वर्ग की रसोई को भी मंहगाई के जरिए ठण्डी करने का दर्द दिया है। उन्होने कहा कि डीजल, पेट्रोल तथा एलपीजी व कामर्शियल सिलेण्डर तथा सीएनजी की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोत्तरी से बाजार में जरूरत की चीजें मंहगी हो गयी हैं। विधायक मोन ने कहा कि प्रदेश में भीषण गर्मी के बावजूद विद्युत आपूर्ति सरकार व पावर कारपोरेशन के कुप्रबंधन के कारण पटरी से उतर चुकी है। उन्होने कहा कि बीजेपी जनता से जुड़ी इन्हीं मूलभूत समस्याओं को हल करने में अपनी विफलता छिपाने के लिए अलोकतांत्रिक कदम उठा रही है। इसके बाद उन्होने कैम्प कार्यालय पर जनसमस्याओं की सुनवाई की। अगई मोड़ पर कार्यकताओं ने विधायक आराधना मिश्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया। क्षेत्र के अगई, उमापुर, पूरे छत्तू, भटनी, लोहंगपुर, नरायनपुर में विधायक आराधना मिश्रा मोना ने जनसंवाद के तहत लोगों को रामपुरखास के विकास की मजबूती की निरन्तरता का भरोसा दिलाया। उन्होने कहा कि वह सांसद प्रमोद तिवारी के साथ मिलकर रामपुरखास को विकास की हर जरूरी योजनाओं से जोड़ते हुए इसकी सुसज्जा के प्रयास जारी रखेंगी। इस मौके पर प्रमुख अमित प्रताप सिंह पंकज, चेयरपर्सन प्रतिनिधि संतोष द्विवेदी, मीडिया प्रभारी ज्ञानप्रकाश शुक्ल, प्रतिनिधि आशीष उपाध्याय, पूर्व प्रमुख भुवनेश्वर शुक्ल, मंटू उपाध्याय, सुरेशचंद्र पटेल, धर्मपाल गौतम, एबादुर्रहमान, आशीष कौशल, दारा सिंह, श्रीराम वर्मा, राकेश चतुवेर्दी, त्रिभु तिवारी, प्रीतेन्द्र ओझा, अतुल शुक्ल, अभिनव शुक्ल, छोटे लाल सरोज, राजकुमार मिश्र, जगदीश नारायण तिवारी, दयाराम वर्मा, अशोक सिंह, राकेश सिंह, आनन्द पाण्डेय, मकदूम सिंह, महादेव मिश्र, राजू माली, विद्याधर पाण्डेय, शशीन्द्र शुक्ला, मुरलीधर तिवारी, गुडडू सिंह आदि रहे।

भाजपा के हिंदुत्व की काट के लिए सपा को गोमाता का सहारा

संवाददाता

एटा। समाजवादी पार्टी (सपा) अपने पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉमूर्ले को हथियार बनाकर भाजपा पर लगातार हमला कर रही है। इसकी काट के लिए भाजपा गैर-यादव और गैर-जाटव मतदाताओं को साधने में जुटी है। वहीं, अब सपा ने भाजपा के हिंदुत्व एजेंडे को टक्कर देने के लिए गोमाता का सहारा लेना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव और डिंपल यादव के बयानों में यह बदलाव साफ झलकने लगा है। हाल ही में गविष्ठी यात्रा पर मैनपुरी आए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के स्वागत कार्यक्रम में सपा सांसदों, विधायकों और नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि सपा अब भाजपा को सनातन और गोमाता के मुद्दे पर घेरने की पूरी कोशिश करेगी। प्रयागराज महाकुंभ में शंकराचार्य के विवाद के बाद से ही अखिलेश यादव भाजपा पर गोमाता के मुद्दे और शंकराचार्य के अपमान को लेकर हमलावर हैं। अखिलेश ने कई मंचों से भाजपा पर शंकराचार्य का अपमान करने और सनातन व गोमाता को केवल चुनावी हथकंडा बनाने का आरोप लगाया है। सपा की यह रणनीति साफ दिख रही है। वहीं, अखिलेश की पत्नी और मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव भी इस मुद्दे को जोर-शोर से उठा रही हैं। उनके बयानों में गोमाता की दुर्दशा का जिक्र बार-बार हो रहा है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने गोमाता की सुरक्षा और उन्हें राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए गविष्ठी यात्रा शुरू की है। कन्नौज पहुंचने पर उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया कि रात गुजारने के लिए उन्हें कोई जगह नहीं दी गई जिसके चलते उन्हें सड़क पर रात बितानी पड़ी। सपा ने इस मामले को तुरंत भुनाया। यात्रा जब औरैया से होती हुई मैनपुरी पहुंची तो सपा के पूर्व विधायक राजकुमार यादव के मैरिज होम पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया।

आयत-ए-मुबाहला हक और बातिल के बीच निर्णायक संघर्ष की उज्ज्वल मिसाल

लखनऊ (संवाददाता)। ऑल इंडिया जुमअतुल कुरैश के जिला अध्यक्ष शहजाद कुरैशी के कार्यालय में आयत-ए-मुबाहला के विषय पर एक आध्यात्मिक एवं वैचारिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता तुफैल अहमद ने की, जबकि संचालन का दायित्व हाफिज अमीर अहमद ने निभाया। कार्यक्रम का शुभारंभ कारी मोहम्मद शम्सुज्जुहा पहलवी की भावपूर्ण कुरआन-ए-करीम की तिलावत तथा मोहम्मद वसीक की नात-ख्वानी से हुआ।मोहम्मद शमीम अख्तर नदवी ने आयत-ए-मुबाहला की व्याख्या करते हुए कहा कि मुबाहला इस्लाम के इतिहास की एक महान और ईमान को मजबूत करने वाली घटना है, जिसमें अल्लाह तआला ने अपने प्रिय नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्य होने को स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया। मुबाहला का अर्थ है कि दो पक्ष अल्लाह तआला के समक्ष यह दुआ करें कि जो झूठा और असत्य पर हो, उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो।उन्होंने मुबाहला की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि जब नजरान के ईसाइयों ने पैगंबर-ए-इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत-ए-हक को स्वीकार करने से इंकार कर दिया, तब अल्लाह तआला ने सूरह आले-इमरान की आयत 61 नाजिल फरमाई और मुबाहला का आदेश दिया। जब नजरान के ईसाइयों ने देखा कि रसूल-ए-अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहहु, हजरत फातिमा जहरा रजियल्लाहु अन्हा, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रजियल्लाहु अन्हुमा के साथ मुबाहला के लिए आ रहे हैं, तो उन पर भय और श्रद्धा का प्रभाव छा गया और उन्होंने मुबाहला से इंकार करते हुए संधि तथा जिज्या को स्वीकार कर लिया।उन्होंने कहा कि इस घटना से अहले बैत अतहार रजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की महानता, श्रेष्ठता और बारगाह-ए-रिसालत में उनके उच्च स्थान का भी स्पष्ट प्रमाण मिलता है। आयत-ए-मुबाहला अहले बैत की शान में नाजिल होने वाली महत्वपूर्ण आयतों में से एक है, जो पूरी उम्मत-ए-मुस्लिमह के लिए मार्गदर्शन का स्रोत है।उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान समय में जब असत्य की शक्तियां विभिन्न रूपों में सत्य को दबाने का प्रयास कर रही हैं, ऐसे समय में वाकध्या-ए-मुबाहला हमें यह शिक्षा देता है कि सच्चाई, ईमानदारी और अल्लाह पर पूर्ण भरोसा रखने वाले लोग कभी असफल नहीं होते। हकद्य की जीत और बातिल की हार अल्लाह तआला का अटल वादा है।कार्यक्रम के संयोजक मोहम्मद आफाक ने अपने संबोधन में कहा कि आयत-ए-मुबाहला मुसलमानों को एकता, सब्र, दृढ़ता और सत्य पर अडिग रहने का संदेश देती है। उन्होंने कहा कि इतिहास इस बात का गवाह है कि असत्य की शक्तियां अस्थायी रूप से मजबूत दिखाई दे सकती हैं, लेकिन अंततः सफलता हमेशा सत्य और न्याय के हिस्से में आती है। उन्होंने युवाओं से विशेष रूप से आग्रह किया कि वे कुरआन-ए-करीम और सीरत-ए-नबवी के संदेश को समझें तथा उसे अपने जीवन में अपनाएं।कार्यक्रम के अंत में देश में अमन-चैन, भाईचारा, राष्ट्रीय एकता, विकास एवं समृद्धि तथा समस्त मानवता के कल्याण के लिए विशेष दुआ की गई।इस अवसर पर शहर की अनेक प्रमुख सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक हस्तियां उपस्थित रहीं, जिनमें मोहम्मद सलमान, मोहम्मद रिजवान कुरैशी, मोहम्मद अरीब सिद्दीकी, सत्यम रोशन, अल्मास, जहांआरा, सबीहा सुल्ताना, बहन जाहिदा तथा फरहाना सिद्दीकी (सपा महिला महासचिव) प्रमुख रूप से शामिल थीं।

मीडिया से पता चला बढ़ गया रेट, भड़के ऊर्जा मंत्री

बिना पूछे कैसे बढ़ाए बिजली के दाम: शर्मा

लखनऊ (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग में बड़ा विवाद खड़ा हो

गया है।बिना पूछे बढ़ा दिए गए बिजली के दाम तो ऊर्जा मंत्री भड़क उठे। हाल ही में सामने आई एक चिट्ठी में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए तीखा प्रहार किया है। मंत्री ने जून के बिजली बिलों में 10 प्रतिशत ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार लागू किए जाने के निर्णय पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने पूछा कि बिना विभाग सेअनुमति या पूर्व जानकारी के महंगाई क्यों की गई।उनका आरोप है कि निर्णय की जानकारी उन्हें अधिकारियों के बजाय टीवी चैनलों और सोशल मीडिया से मिली, जो सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला है। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि विभाग के फैसलों की जानकारी उन्हें क्यों नहीं दी गई, जबकि यह निर्णय विभाग की ही ओर से लिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग कीमुख्यालय से उनकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर ऐसे बड़े निर्णय लिए गए हैं, जो जनता के हितों के खिलाफ हैं। शर्मा ने चेयरमैन की कार्यशैली, अनुभवी कर्मचारियों को हटाने और विभाग की व्यवस्था में लापरवाही को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि बिजली व्यवस्था में हो रही लापरवाही किसी कीमत पर स्वीकार नहीं। पत्र जिसकी तारीख 2 जून है, जिसका विषय है-शासन की मंशा के विपरीत वाली कार्यशैली बंद करने हेतु। अध्ययन के अनुसार 29 मई को पावर कारपोरेशन ने निर्देश जारी किया था, जिसमें कहा था कि जून 2026 के बिलों में 10 प्रतिशत एफपीपीएएस सरचार्ज लगेगा। निर्णय के बाद समाचार पत्रों, सोशल मीडिया पर सरकार के विरुद्ध नकारात्मक खबरों का माहौल बन गया।मंत्री का कहना है कि ऐसे व्यापक प्रभाव डालने वाले निर्णय की विभागीय स्तर पर अनुमति या सूचना क्यों नहीं ली गई।

प्री-मानसून की दस्तक... फिर भी नहरें सूखीं, किसानों की उम्मीदों पर पानी फेरती व्यवस्था

संवाददाता

कौशाम्बी। प्री-मानसून की दस्तक के साथ किसानों ने खरीफ फसलों की तैयारी शुरू कर दी है लेकिन जिले की अधिकांश नहरों और रजबहों में अब तक पानी नहीं पहुंच सका है। भीषण गर्मी के बीच सूखी नहरों में धूल उड़ रही है।धान की नर्सरी तैयार करने और खेतों की सिंचाई करने वाले किसानों की चिंता बढ़ गई है। निचली गंगा कमांड की मंझनपुर और करारी रजबहों समेत जिले की कई नहरों में अभी तक पानी नहीं छोड़ा गया है। खेतों में बोआई की तैयारी कर चुके किसानों को समय पर सिंचाई न मिलने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धान की रोपाई का समय नजदीक आने के बावजूद नहरों का सूखा रहना किसानों की चिंता बढ़ा रहा है। किसान अनिल कुमार, प्रदीप, हरीलाल, राम खेलावन और शीतला प्रसाद का कहना है कि हर वर्ष खरीफ सीजन से पहले नहरों में पानी पहुंचाने के दावे किए जाते हैं। हकीकत यह है कि खेतों तक पानी समय से नहीं पहुंच पाता। यह हालात सिर्फ मंझनपुर और करारी तक सीमित नहीं है। नेवादा, चायल, मूरतगंज, कौशाम्बी और मंझनपुर ब्लॉक की कई नहरों व रजबहों में भी पानी नहीं पहुंचा है। मंझनपुर रजबहा में करीब तीन महीने से पानी नहीं छोड़ा गया। इस समय धान की बेहन के साथ उर्द, मूंग और पिपरमिंट की फसलों की सिंचाई के लिए पानी की ज्यादा जरूरत है। - शीतला प्रसाद मिश्र, किसान भैला मकदूमपुर करारी रजबहा में करीब तीन साल से पानी नहीं आया। किसानों को सिंचाई के लिए दूसरे के प्राइवेट नलकूप से अधिक पैसा देकर सिंचाई करनी पड़ती है। अब तो सिर्फ बारिश ही सहारा है।

हिन्दी दैनिक
संयम भारत
मुद्रक, प्रकाशक एवं स्वामी श्रीकान्त तिवारी, विपीन इंटरप्राइजेज 15/1/7 मास्टर जहूरूल हसन रोड कटरा प्रयागराज उत्तर प्रदेश से मुद्रिम एवं 68ए/61ए महावीरन गली मुटट्ीगंज प्रयागराज उत्तर प्रदेश से प्रकाशित।
संपादक
श्रीकान्त तिवारी
मो.-9415030710
Email-sanyambharatmedia@gmail.com
संयम भारत द्वारा प्रकाशित समस्त समाचारों हेतु उत्तरदायी एवं सभी विवाद प्रयागराज न्यायालय के अधीन ही होंगे।